● वर्ष-2
● अंक-277
रायपुर, बुधवार
12 जुलाई 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पूजा स्थल कानून की संवैधानिकता कोर्ट में

चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जवाब देने के लिए समय दिया

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र को 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 31 अक्तूबर तक का समय दिया है। दरअसल, वर्शिप एक्ट किसी भी पूजा स्थल को फिर से प्राप्त करने या उसमें बदलाव करने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाता है।

इससे पहले मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों को सुना। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सरकार एक व्यापक जवाब दाखिल करने पर विचार कर रही है। सॉलिसिटर जनरल की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने केंद्र को मामले में दायर याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया।

याचिकाओं पर हो अंतिम सुनवाई

दूसरी ओर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, %केंद्र मामले में देरी करवा रहा है। इसलिए कोर्ट को चाहिए कि वह इन याचिकाओं को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें। इस पर पीठ ने कहा, केंद्र मामले को स्थगित करने की मांग कर रहा है। उन्हें जवाबी हलफनामा दायर करने दें। देखते हैं उसमें क्या है।

बता दें कि इससे पहले नौ जनवरी को शीर्ष

अदालत ने केंद्र सरकार से पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के कुछ प्रावधानों के खिलाफ जनहित याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। इसके लिए कोर्ट ने केंद्र को फरवरी के अंत तक का समय दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने छह याचिकाएं सीज कीं

गौरतलब है उच्चतम न्यायालय ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ दायर वकील अश्विनी उपाध्याय और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिकाओं सहित छह याचिकाओं को सीज कर लिया है। अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में विनती की है कि पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की धारा 2, 3, 4 को रद्द कर दिया जाए।

असंवैधानिक है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट

इतना ही नहीं उपाध्याय ने यह भी दावा किया कि पूरा कानून असंवैधानिक है। वहीं, स्वामी चाहते हैं कि अदालत कुछ प्रावधानों को %रीड डाउन% करे, ताकि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद पर हिंदू अपना दावा कर सकें।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से पेश हुए वकील एजाज मकबूल ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मालिकाना हक मामले में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद केस में भी पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 का हवाला दिया है। ऐसे में इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

क्या है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट?

प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार के समय बनाया गया था। इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म की उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। इस कानून के मुताबिक आजादी के समय जो धार्मिक स्थल जैसा था वैसा ही रहेगा और उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।

शाही ईदगाह मस्जिद समिति ने सुको में हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

प्रबंधन ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह समिति ने मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि भूमि विवाद से संबंधित सभी याचिकाओं को उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालय मथुरा से अपने पास स्थानांतरित करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह ने वकील आरएचए सिकंदर के माध्यम से याचिका दायर की। ईदगाह ट्रस्ट ने 26 मई को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत उसने कृष्ण जन्मभूमि विवाद से संबंधित ऐसे सभी मामलों को जिला न्यायालय मथुरा, उत्तर प्रदेश से अपने पास स्थानांतरित कर लिया था।स्थानांतरण आवेदन को इस तथ्य के बावजूद उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी कि जिस मुकदमे से स्थानांतरण आवेदन निकला था, उस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक 03.08.2022 के आदेश के तहत रोक लगा दी थी। आक्षेपित निर्णय दो अपीलीय चरणों को हटा देता है और अन्य मुकदमों को भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर देता है, जिसके लिए कोई स्थानांतरण आवेदन दायर नहीं किया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की भविष्यवाणी में शामिल होकर कि यदि मुकदमे का फैसला ट्रायल कोर्ट द्वारा ही किया जाता है, तो इसमें काफी समय लगेगा, इस पर विचार किए बिना ही आक्षेपित निर्णय पारित कर दिया गया है। केवल 26.05.2022 को पंजीकृत किया गया था और उसमें कार्यवाही को बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने 03.08.2022 के आदेश के माध्यम से रोक दिया था जो 01.05.2023 तक लागू रहा।

पंचायत चुनावः तृणमूल कांग्रेस सबसे आगे

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। यहां आठ जुलाई को कड़ी सुरक्षा के मतदान संपन्न हुआ था। उसमें लगभग 5.67 करोड़ मतदाताओं ने पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में 73,887 सीटों के लिए मतदान किया था। इन सीटों पर दो लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए भाग्य का फैसला आज होगा। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के मतगणना के दिन भी जगह-जगह से हिंसक झड़पों जारी रहीं। मतगणना से पहले ही हिंसा की खबरें आने लगी थीं। दिनहाटा, हावड़ा, बशीरहाट, कूचबिहार, मालदा, दक्षिण 24 परगना जिले के विभिन्न मतगणना केंद्रों पर बमबाजीझड़पों की खबरें हैं। कई जगह सुरक्षाबलों को लाठीचार्ज तक करनी पड़ी। इस बीच मतगणना मंगलवार सुबह 8 बजे से शुरू हुई। राज्य में कुल 339 मतगणना केंद्रों पर मतगणना जारी है। अब तक मिले रुझानों के मुताबिक सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाए हुए है। विपक्षी पार्टिया भाजपा, सीपीएम और कांग्रेस काफी पीछे चल रही हैं।

राज्य चुनाव आयोग की ओर से घोषित परिणामों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस ने 16,000 से अधिक ग्राम पंचायत सीटों पर जीत हासिल कर ली है। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस 3,000 सीटों पर आगे चल रही है। भाजपा 3,700 से अधिक सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है और 800 से अधिक सीटों पर आगे चल रही है। वाम मोर्चा ने 1300 से अधिक सीटों पर जीत हासिल की है, जिनमें से अकेले सीपीआई (एम) ने 1200 से अधिक सीटों पर जीत हासिल की है।

इन दिनों

सौरभ शर्मा

महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना

भारत के जनांकिकी आंकड़ों के मुताबिक भारत की औसत आयु 28 वर्ष है और इस नाते युवा शक्ति इस देश को आगे ले जाने में अपना बड़ा योगदान दे सकती है। दुनिया भर में जनांकिकी को आर्थिक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। इस लिहाज से भारत में आर्थिक शक्ति की बड़ी संभावना है। जनांकिकी की तरक्की इस बात पर निर्भर करती है कि आधी आबादी की हिस्सेदारी कार्यक्षेत्र में कितनी है। इस दृष्टि में भारत में अभी महिलाओं की केवल 17 फीसदी आबादी कार्यक्षेत्र में है जबकि चीन की 40 प्रतिशत महिला आबादी कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की ग्रामीण विकास योजनाओं से सीधे महिलाओं की बड़ी आबादी आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हो गई है। इसका सबसे सुंदर उदाहरण गौठान और रीपा के माध्यम से आर्थिक गतिविधियां हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद स्व-सहायता समूहों की संख्या तेजी से बढ़ गई। दिसंबर 2018 के बाद से अब तक 13 लाख से अधिक महिलाएं इन समूहों से जुड़ चुकी हैं। इस तरह से कार्यशील आबादी की संख्या में तेजी से विस्तार आया है। इस बड़ी आबादी के कार्यशील गतिविधियों में लगे होने का अर्थव्यवस्था को लाभ तो होता लेकिन जब तक इनके लिए व्यवस्थित बाजार मुहैया नहीं कराया जाता तब तक यह लाभ प्रभावी नहीं हो पाते। छत्तीसगढ़ सरकार ने इनके लिए बाजार प्रदान किया। हर जिले में सी-मार्ट आरंभ किये गये। इन सी-मार्ट के माध्यम से हर क्षेत्र के खास उत्पादों को जगह मिली। उदाहरण के लिए बस्तर के दंतेवाड़ा में यदि भूमगादी समूह से जुड़ी कोई महिला जैविक चावल का विक्रय कर रही है तो उसके लिए बाजार केवल अपने आसपास के क्षेत्र तक नहीं है अपितु पूरा छत्तीसगढ़ और इसके बाहर भी बाजार उपलब्ध है। इसके साथ ही प्रशिक्षण का पक्ष भी महत्वपूर्ण है। जब महिलाएं एसएचजी से जुड़ती हैं तो बैंकिंग गतिविधियों से भी जुड़ती हैं एकाउंटेंसी से भी परिचित होती हैं और मार्केट को भी समझ पाती हैं। इस तरह पूरी तरह से आर्थिक कार्यकलापों के लिए दक्ष बनाने अपने को तैयार कर पाती हैं। जब महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं तो अपनी बेटियों को भी इस दिशा में तैयार कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में स्कूल के अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और महिलाओं में बढ़ी जागरूकता का प्रभाव स्कूलों में दर्ज संख्या से पता चलती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में 10 से अधिक साल तक पढ़ाई करने वाली लड़कियों की संख्या में 36.9 प्रतिशत वृद्धि हुई है। महिलाओं के आगे आने से आर्थिक रूप से सबल होने से उनकी सामाजिक स्थिति भी सशक्त हो रही है। मुख्यमंत्री से भेंट मुलाकात के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी संख्या में पुरुष हितग्राही अनुभव साझा करते हैं उतनी ही संख्या में महिला हितग्राही भी अपना अनुभव साझा करते हैं। इन सभाओं को देखकर महसूस होता है कि छत्तीसगढ़ का समाज सचमुच समतामूलक समाज है जहां महिलाओं और पुरुषों की कार्यक्षेत्र में बराबरी की भागीदारी हैं और दोनों ही मिलकर अपने प्रदेश के विकास की गाथा को गढ़ रहे हैं। महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं और आर्थिक रूप से सक्षम होने की वजह से उनके पास भी परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने की शक्ति आ गई है। चाहे बच्चों की पढ़ाई का मामला हों, उनके लिए ज्वैलरी खरीदी हो। वे निर्णय ले रही हैं। अपने सपनों को पूरा करने की जो शक्ति उनके भीतर आई है उससे उनके जीवन में खुशियां भी बढ़ी हैं। गौठानों में आजीविकामूलक गतिविधियों का ट्रेंड देखें तो यह साफ होता है कि महिलाएं लगातार अपनी आर्थिक गतिविधियों का विस्तार कर रही हैं। जिन समूहों की महिलाएं वर्मी कंपोस्ट तैयार करती थीं। उन्होंने मशरूम का उत्पादन आरंभ कर दिया। तेल पिराई का काम करने लगीं। इस तरह अपने आसपास की बाजार की जरूरतों को भांपते हुए अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाया। छत्तीसगढ़ में उद्यमशील समाज के निर्माण में अब इन महिलाओं की अहम भूमिका हो गई है।

प्रमुख समाचार

370 पर शेहला रशीद और शाह फैसल ने याचिका ली वापस

नईदिल्ली। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के खिलाफ याचिकाकर्ताओं में शामिल शाह फैसल और शेहला रशीद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिकाएं वापस ले ली हैं। आईएएस

अधिकारी शाह फैसल और जेएनयू के पूर्व छात्र संघ नेता शेहला रशीद ने अपनी याचिकाएं वापस ले लीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त से अनुच्छेद 370 को खत्म करने पर रोजाना सुनवाई शुरू करने का फैसला किया। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से जम्मू और कश्मीर राज्य के विशेषाधिकार छीन लिए गए और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। 2009 में सिविल सेवा (यूपीएससी) परीक्षा में टॉप करने वाले पहले कश्मीरी शाह फैसल ने जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त करने के केंद्र सरकार के 5 अगस्त के फैसले के बाद 2019 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सिविल सेवक ने सरकार पर भारतीय मुसलमानों को हाशिए पर रखने और सार्वजनिक संस्थानों में हस्तक्षेप करने का भी आरोप लगाया।

कांग्रेस ने शुरू की महाराष्ट्र में चुनावी तैयारी

मुंबई। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक का दौर जारी है। आज महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक के बाद कांग्रेस ने चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बनाई है। कांग्रेस फिलहाल

महाराष्ट्र में महा विकास आघाडी गठबंधन के भीतर है। महा विकास आघाडी में शरद पवार गुट की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना शामिल है। बैठक के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने साफ तौर पर कहा कि मोदी सरकार से जनता परेशान है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को वह जनता के बीच उठाएगी। खड़गे ने ट्वीट किया, ''भाजपा ने अपनी 'वॉशिंग मशीन' का इस्तेमाल कर, महाराष्ट्र के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी इस राजनीतिक जालसाज़ी का बराबर जवाब देगी। महाराष्ट्र की जनता जनादेश पर भाजपा द्वारा किए गए लगातार हमलों का कड़ा राजनीतिक उत्तर देगी।'' उन्होंने कहा, ''हमारे नेता और कार्यकर्त्ता, महाराष्ट्र की जनता को उसकी अपनी सरकार वापस दिलाएंगे।

गुजरात में अब 5 के बजाय 10 लाख तक मुफ्त इलाज

नईदिल्ली। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने गुजरात के आयुष्मान कार्ड धारकों को बड़ा उपहार देते हुए इसकी लाभ की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर दिया है। आज 11 जुलाई से यह नियम गुजरात के सभी आयुष्मान कार्ड धारक परिवारों पर लागू हो गया है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल ने गाँधीनगर में एक कार्यक्रम में गुजरात सरकार के इस नए पहल की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री मनोज अग्रवाल, हेल्थ कमिश्नर सुश्री शाहमिना हुसैन, नेशनल हेल्थ मिशन की डायरेक्ट डॉ. रेम्या मोहन, समेत वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। गुजरात सरकार के जन स्वास्थ्य सुरक्षा कवच को लेकर इस सबसे बड़े कदम तहत प्रति आयुष्मान कार्ड धारक परिवार गुजरात के साथ-साथ देश के किसी भी कोने में मौजूद अस्पताल, बशर्ते वह अस्पताल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एम्पैनल्ड हो, में 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि, 2,471 प्रकार के मेडिकल प्रोसीजर्स का लाभ आयुष्मान कार्ड धारक परिवार ले सकते हैं।

यूसीसी पर विधि आयोग को मिले 46 लाख सुझाव

नई दिल्ली। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर विचार भेजने की समय सीमा दो दिन में समाप्त होने के बाद विधि आयोग को अब तक करीब 46 लाख प्रतिक्रियाएं मिल चुकी हैं। आयोग आने वाले दिनों में कुछ संगठनों और लोगों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुला सकता है। सूत्रों ने बताया कि इनमें से कुछ निमंत्रण पत्र पहले ही भेजे जा चुके हैं। सोमवार शाम तक समिति को करीब 46 लाख प्रतिक्रियाएं मिल चुकी थीं। विधि आयोग ने 14 जून को राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मुद्दे पर सार्वजनिक और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों सहित हितधारकों से राय मांगकर एक नई परामर्श प्रक्रिया शुरू की थी। इससे पहले, 21वें विधि आयोग ने इस मुद्दे की जांच की और दो मौकों पर सभी हितधारकों के विचार मांगे। 21वें विधि आयोग का कार्यकाल अगस्त 2018 में समाप्त हो गया था। अगस्त 2018 में परिवार कानून के सुधार पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था। आयोग ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा था, चूंकि इस विषय की प्रासंगिकता और महत्व व इस विषय पर अदालत के विभिन्न आदेशों को ध्यान में रखते हुए उक्त परामर्श पत्र जारी होने की तारीख से तीन साल से अधिक समय बीत चुका है।

आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक ऊटी में

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की अखिल भारतीय ''प्रांत प्रचारक बैठक'' इस वर्ष 13 से 15 जुलाई को तमिलनाडु के कोयम्बटूर के निकट ऊटी में आयोजित हो रही है जिसमें संगठनात्मक विषयों

पर चर्चा होगी। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने एक बयान में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, '' यह वार्षिक बैठक मुख्यत: संगठनात्मक विषयों पर चर्चा करने हेतु प्रतिवर्ष आयोजित होती है। '' आंबेकर ने कहा कि बैठक में इस वर्ष हुए संघ शिक्षा वर्गों के कार्यों की समीक्षा, संघ शताब्दी कार्यविस्तार योजना की अभी तक हुई प्रगति, शाखा स्तर के सामाजिक कार्यों का विवरण और परिवर्तन से जुड़े अनुभवों का आदान-प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा होगी। आरएसएस की स्थापना सितंबर 1925 में हुई थी और संगठन 2025 में अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मनाने की तैयारी कर रहा है। बैठक के बारे में आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख ने बताया कि इसमें आगामी चार-पांच माह के कार्यक्रमों की योजना तथा वर्तमान स्थिति के संदर्भ में भी चर्चा होगी।

संघ विरोध के बहाने कांग्रेस की दुर्गति कर रहे दिग्विजय सिंह

सिद्धार्थ शंकर गौतम

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक गुरु गोलवलकर के विरुद्ध विषवमन करते हुए कांग्रेस को प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पूर्व अचंभित करते हुए पशोपेश में धकेल दिया है। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना, किसानों के लिए राहत पैकेज, वनवासी समाज की चिंताओं, समान नागरिक संहिता, वर्तमान भाजपा सरकार के विरुद्ध असंतोष जैसे मुद्दों पर विधानसभा चुनाव में उतरने को तैयार कांग्रेस को दिग्विजय सिंह के बयान से झटका लगा है क्योंकि अब प्रदेश में सर्वाधिक मजबूत संघ परिवार और भाजपा के संगठन की दोहरी चुनौती से उसे जूझना पड़ रहा है। संघ परिवार और भाजपा नेतृत्व का कहना है कि बोल भले ही दिग्विजय सिंह के हों किन्तु संघ पर द्वेषपूर्ण मिथ्या आरोप लगाने की नीति कांग्रेस की है जिसे वे लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। हालाँकि देर-सवेर कांग्रेस इसे दिग्विजय सिंह की निजी सोच बताकर इस विवाद से पल्ला झाड़ लेगी किन्तु संघ पर झूठे आरोप लगाने से उसके चुनावी मुद्दे अवश्य प्रभावित होंगे। इससे पूर्व दिग्विजय सिंह ने 26 नवंबर, 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले में संघ का हाथ बताकर सनसनी फैला दी थी। उस कालखंड में उनके द्वारा पोषित %हिंदू आतंकवाद% का झूठ प्रतिवर्ष 26/11 को सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया में ट्रेंड होता है। कांग्रेस पर मुस्लिम परस्त राजनीति का जो ठप्पा लगा है उसके मूल में कहीं न कहीं दिग्विजय सिंह का हिंदुत्व और संघ के प्रति दुर्भावनावश आरोप पूर्ण रवैया है जिसे समग्र हिंदू समाज की अस्मिता से जोड़ दिया गया है।

चूंकि संघ हिन्दू समाज के बृहत्तर वर्ग तक पहुंच बना चुका है अत: दिग्विजय सिंह जब भी संघ पर आरोप मढ़ते हैं, उसे हिंदू समाज पर हमला माना जाता है। कांग्रेस की यही सबसे बड़ी दुविधा है क्योंकि सत्ता से लंबे समय से दूर पार्टी जब भी %सॉफ्ट हिंदुत्व% का सहारा लेकर जनता के बीच जाती है, दिग्विजय सिंह तथा उनके जैसे अन्य पार्टी नेता हिंदुत्व के प्रतीक बन चुके संघ पर निशाना साधकर अपनी ही पार्टी के प्रयासों की हवा निकाल देते हैं। दिग्विजय सिंह ने गुरूजी का चित्र ट्विटर पर साझा करते हुए एक काल्पनिक कथन लिख दिया कि एम एस गोलवलकर ने अपनी पुस्तक 'we and our nationhood identified' में स्पष्ट लिखा है कि जब भी सत्ता हाथ लगे तो सबसे पहले सरकार की धन संपत्ति, राज्यों की जमीन और जंगल अपने दो तीन विश्वसनीय धनी लोगों को सौंप दें। 95% जनता को भिखारी बना दें, उसके बाद सात जन्मों तक सत्ता हाथ से नहीं जाएगी। इसी चित्र में गोलवलकर के चित्र के साथ दूसरा झूठ यह लिखा है कि मैं सारी जिंदगी अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए तैयार हूँ लेकिन जो दलित, पिछड़ों और मुसलमानों को बराबरी का अधिकार देती हो ऐसी आजादी मुझे नहीं चाहिए। हालांकि इस

सरासर झूठे और आपत्तिजनक ट्वीट के चलते दिग्विजय सिंह पर इंदौर, राजगढ़, गुना और उज्जैन में एफआईआर दायर हो चुकी है तथा प्रदेश के अन्य शहरों में भी स्वयंसेवक उन पर भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। आश्चर्य इस बात का भी है कि दिग्विजय सिंह ने इतने पर भी अभी तक झूठा ट्वीट हटाया नहीं है बल्कि वे माफी मांगने के बजाय संघ के प्रति और अधिक आक्रामक होकर झूठ फ़ैलाने में लग गए हैं। अव्वल तो दिग्विजय सिंह ने गुरूजी की जिस पुस्तक 'we and our nationhood identified' का हवाला दिया है वह गुरूजी ने लिखी ही नहीं है। गुरूजी की पुस्तक का नाम 'we and our nationhood defined' है। इससे यह साफ होता है कि दिग्विजय सिंह ने फेक न्यूज की फैक्ट्री का राजा साहब बनने की ठान ली है। हालांकि उनका झूठ बेनकाब हो गया है किन्तु बड़ा प्रश्न यह है कि एक अनुभवी राजनेता को आखिर ऐसा झूठ प्रचारित करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? दरअसल, देश में समान नागरिक संहिता का मुद्दा बहस के केंद्र में है और दिग्विजय सिंह यह जानते हैं कि देश-प्रदेश का बहुसंख्यक समाज इसके लागू होने के पक्ष में है। यदि यह लागू हुआ तो मुस्लिम समाज की प्रतिक्रिया के अलावा वनवासी समाज में भी विरोध के स्वर उठ सकते हैं। चूंकि वनवासी समाज में षड्यंत्र के तहत समान नागरिक संहिता के नाम पर भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है किन्तु संघ परिवार के वनवासियों के बीच शैक्षणिक-सामाजिक कार्यों से कांग्रेस, वामपंथी दलों, सिविल सोसायटी, ईसाई मिशनरी, इस्लाम के प्रचार-प्रसार के मंसूबों पर पानी फिर रहा है अत: संघ को ही बदनाम करके वनवासी समाज के बीच उसकी छवि मलिन कर उन्हें दिग्भ्रमित करने की मंशा है। मध्य प्रदेश, जहां डेढ़ करोड़ से अधिक वनवासी जनसंख्या है, वहां चुनावी वर्ष में यदि वनवासी समाज में पैठ बना चुके संघ के विरोध में माहौल बनता है तो यह कांग्रेस के लिए मुफीद हो सकता है।

इसके अलावा हाल ही में सीधी में कथित भाजपा कार्यकर्ता केदार शुक्ला द्वारा दलित युवक पर पेशाब करने का जो वीडियो वायरल हुआ, उससे भी दिग्विजय सिंह को दलितों-पिछड़ों के पक्ष में बोलने का और संघ पर आरोप लगाने का अवसर दे दिया है। दिग्विजय सिंह जिन गुरू गोलवलकर के विरुद्ध जो आरोप लगा रहे हैं, उनका जीवन इसके ठीक उलट रहा है। गुरूजी के समस्त भाषणों, बौद्धिकों, वक्तव्यों में समाज में व्याप्त ऊँच-नीच का प्रबल विरोध रहा है। सामाजिक समरसता बढ़ाने के उद्देश्य से गुरुजी की प्रेरणा से वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ जैसे अनेक संगठन प्रारंभ हुए जिन्होंने हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। खैर, यहाँ प्रश्न गुरूजी के योगदान का नहीं है। प्रश्न है कि दिग्विजय सिंह ने जिस सोच के चलते गुरूजी के बहाने संघ को घेरने की चेष्टा की है।

निर्माण कार्य सतत प्रक्रिया, उसे सहेजने और संवारने की आवश्यकता : रंजना

- **नारी शक्ति की प्रतीक हैं रंजना साहू, जिन्होंने हमें गौरवान्वित किए : दमयंती साहू**
- **रंजना साहू विधायक का दायित्व निष्ठा पूर्वक निर्वहन कर रही है : मुरारी यदु**

धमतरी। गांव का विकास सर्वोपरि होता है, इस बात को कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए दमयंती केशव साहू जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि विधायक रंजना साहू ने हमारे ग्राम रींवागहन को लगभग दो करोड़ रुपए के विकास कार्य की सौगात हम सभी ग्रामवासियों को दिए हैं यह उनका हमारे गांव के प्रति स्नेह और बड़प्पन है। जिसका लाभ समस्त ग्रामवासियों को मिला और सर्वाधिक कार्य हमारे गांव को दिए, जिसमें हमारे बहुप्रतीक्षित मांगों को उन्होंने पूरा किया। विधायक नारी शक्ति की पहचान है जिन्होंने पूरे धमतरी विधानसभा को गौरवांवित किए हैं।

उक्त बातें जिला पंचायत सदस्य ने अपने निज ग्राम रींवागहन में लोकार्पण एवं भूमि पूजन निर्माण विधायक द्वारा किए जाने पर कहीं। ग्राम रीवागहन में मुख्य मार्ग से बस्ती की ओर सीसी रोड निर्माण कार्य का भूमिपूजन, शीतला माता मंदिर प्रांगण में शेड निर्माण कार्य का भूमिपूजन, साहू समाज सामुदायिक भवन में शेड निर्माण कार्य का भूमिपूजन, प्राथमिक शाला 03 अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य का लोकार्पण एवं आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 भवन निर्माण कार्य का लोकार्पण मुख्य अतिथि विधायक श्रीमती रंजना साहू की उपस्थिति में संपन्न हुआ। सर्वप्रथम विधायक सहित अतिथियों ने गांव के आराध्य माता शीतला की पूजा अर्चना कर भूमिपूजन लोकार्पण संपन्न किया गया।

विधायक रंजना साहू ने कहा कि निर्माण कार्य सतत प्रक्रिया है किंतु उसको सहेजने और सवारने की आवश्यकता स्थानीयों की होती हैं, निरंतर निर्माण कार्य होते रहते हैं उनका सदुपयोग करते हुए उसके रंगरोहन पर ध्यान देकर सुरक्षित रखना वह स्वयं की जिम्मेदारी होती है। विधायक ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की अनेक योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दिए।

आमदी मंडल अध्यक्ष मुरारी यदु ने बताया कि रंजना साहू विधायक का दायित्व निष्ठा पूर्वक निर्वहन कर रही है, क्षेत्र के सभी बहुप्रतीक्षित मांग को विधानसभा के पटल पर रखकर निर्माण कार्य करा रही है सदैव सक्रियता से कार्य करते हुए जनहित का कार्य किए हैं। नगर निगम पूर्व महापौर अर्चना चौबे ने बताया कि छत्तीसगढ़ में सबसे सक्रिय रूप में कार्य करते हुए विधायक रंजना साहू ने यह सिद्ध कर दिया कि नारी शक्ति आगे बढ़ रही है, और 21वीं सदी महिलाओं की हैं, यह प्रमाण भाजपा द्वारा रंजना साहू को प्रदेश प्रवक्ता बनाए जाना तदुपरांत विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा विधानसभा पटल पर में उत्कृष्ट विधायक चुना जाना यह उसकी सक्रियता का प्रमाण है।

इस लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम में मुख्य रूप से आमदी मंडल महामंत्री अमन राव, जनपद सदस्य जागेश्वरी राकेश साहू, ग्राम पटेल चेतन साहू, कुरमातराई ग्राम पटेल यक्ष कुमार साहू, ग्राम विकास समिति अध्यक्ष जवाहर लाल साहू,सुखदेव राम साहू, शंकर लाल साहू, नारायण साहू, कलीराम साहू, विजय साहू, कोमल यादव, दूज राम, भगवती साहू, ओम प्रकाश साहू, लालाराम साहू, केशव साहू, उपसरपंच सेवरी साहू, हिमकेश साहू, तेजराम यादव, लुकेश्वर साहू, भीषम साहू, नारद ध्रुव, उमेश्वरी साहू, मोतीलाल साहू, हरी राम साहू, अनीता नायक, नारायणी साहू, लक्ष्मी यादव, सरस्वती गौतम, डोमार ध्रुव, संतराम ध्रुव, भूपेंद्र साहू, दुखुराम साहू, कलिंदरी कोर्राम, ग्रामीण साहू समाज, शीतला सेवा समिति, बोल बम कांवरिया समिति, जस गीत सेवा समिति, ग्राम विकास समिति, महिला सेवा समिति के सदस्य सहित ग्रामीण उपस्थित रहे।

सड़क हादसे में गई ग्रामीण की जान का जिम्मेदार कोई है तो राज्य सरकार है : विधायक

धमतरी। क्षेत्र की कोलियारी खरेंगा मार्ग के सड़क की मांग बहुप्रतीक्षित है,सोमवार को फिर एक ग्रामीण ने दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवाई है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह 8-8:30 बजे के आस पास अपने काम पर जा रहे ग्रामीण को तेज रफ्तार हाईवा ने अपनी चपेट में ले लिया और ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई,इस क्षेत्र की सड़क की मांग बहुत लंबी है ग्रामीणों से लेकर विधायक तक सभी ने आंदोलन कर इस सड़क के लिए लड़ाई लड़ी है परंतु इतने हादसों के बाद भी सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है,बीते वर्ष विधायक ने झुरानवागांव से लेकर कोलियारी तक ग्रामीणों के साथ पदयात्रा भी की थी तो वहीं विधानसभा में भी इस विषय को गंभीरता से उठाया तो समय समय पर विभागीय मंत्री से भी मिल कर मांग के बावजूद इसकी स्वीकृति अब तक नहीं मिली। जारी प्रेस नोट में विधायक श्रीमती रंजना साहू ने कहा इस सड़क हादसे में गई ग्रामीण की जान का कोई जिम्मेदार है तो वो राज्य सरकार है। ना जाने कितने लोगों ने इस बदहाल सड़क पर अपनी जान गंवाई है हमने शासन से बार बार इस विषय को गंभीरता से लेकर जल्द इसकी प्रशासनिक स्वीकृति देने की मांग की है,एडीबी में शामिल होने के बाद भी चार साल से यह सरकार इस सड़क की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दे रही है,न जाने और कितने हादसों का इंतज़ार कर रही है ये सरकार। वहीं भाजपा मछुआरा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नेहरू निषाद ने कहा आज का सड़क हादसा अत्यंत पीड़ादायक है,वे कांग्रेसी जो इस सड़क पर धान बोने की नौटंकी करते थे आज साढ़े चार साल से राज्य में उनकी सरकार है फिर क्यों सड़क की स्वीकृति नहीं मिल रही है। भाजपा भोथली मंडल अध्यक्ष हेमंत चंद्राकर ने कहा यह अवैध रेत उत्खनन और ओवरलोड हाईवा की वजह से घटना हुई है जब माइनिंग अभी बंद है तो उस दरम्यान रेत से भरी हाईवा सड़क में कैसे रात को हज़ारों की संख्या में तेज रफ्तार हाईवा इस रोड में माइनिंग बंद होने के बावजूद चलती है अधिकारियों से लेकर सरकार तक सभी की मिली भगत से रेत का अवैध कारोबार का खामियाजा ग्रामीण को अपनी जान गंवा कर देना पड़ा है।

10 हजार मांगते हो, शर्म नहीं आती, सस्पेंड करा दूंगा, नौकरी नहीं मिलेगी : विधायक

मनेंद्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले में सोमवार को हुए पट्टा वितरण कार्यक्रम के दौरान विधायक विनय जायसवाल एक पटवारी पर भड़क गए। उन्होंने पटवारी को मंच पर बुलाया और जमकर फटकार लगाई। कहा कि 10 हजार मांगते हो, शर्म नहीं आती। यह भी कहा कि सस्पेंड करा दूंगा, 10 साल तक नौकरी नहीं मिलेगी। उन्होंने एसडीएम राजस्व को कार्यवाही करने के लिए भी कहा। इसके बाद पटवारी से बोले कि यहां से चले जाओ, दोबारा शक्ल मत दिखाना।

पट्टा वितरण कार्यक्रम में पहुंचे थे विधायक

दरअसल, मनेंद्रगढ़ विकासखंड के ग्राम खड़गवां के सामुदायिक भवन में सोमवार को पट्टा वितरण कार्यक्रम था। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय किसान और ग्रामीण पहुंचे थे। वहीं विधायक विनय जायसवाल भी शामिल हुए थे। इस दौरान मंगोरा. नारायणपुर, भौता, छिपछीपी, बंजी बुंदेली से आए ग्रामीणों ने पटवारी सुदामा साहू के खिलाफ विधायक विनय जायसवाल को लिखित शिकायत दी। आरोप लगाया कि राज्य सरकार की योजनाओं को जमीनी रूप देने में पटवारी हर काम की 10 हजार रुपये रिश्वत लेता है।

पूछा- मैडम ने कहा क्या पैसे लेने को

इसके बाद विधायक विनय जायसवाल ने मंच पर ही पटवारी सुदामा साहू को भी बुला लिया और भड़क गए। विधायक ने पटवारी को जमकर फटकार लगाई। कहा कि, तुम्हारी शिकायत आई है। शर्म आनी चाहिए तुमको। 10 हजार रुपये मांगते हो, ग्रामीणों से। क्या ग्रामीण झूठ बोल रहें। तुम इतने यंग हो, पटवारी हो। वेतन मिलता है। किसने कहा है, तुमसे पैसा लेने के लिए, मैडम ने कहा है, मैंने कहा है? फिर विधायक एसडीएम राजस्व नयन तारा सिंह तोमर की ओर पलटे और कहा कि इस पर तत्काल कार्यवाही करें।

पता चला कि घूस मांगते हो तो छोड़ूंगा नहीं

विधायक विनय जायसवाल ने पटवारी से कहा कि, ये सब किसान हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं। इस पर पटवारी ने कहा कि, शिकायत झूठी है। इसके बाद विधायक और नाराज हो गए। कहा कि झूठा शिकायत कैसे करेंगे। मैं खुद मौके पर गया हूं। गरीब आदमी झूठी शिकायत करेगा। पटवारी हो, पटवारी की तरह रहो। एक-एक को बता रहा हूं कि पता चला कि घूस मांगते हो तो छोड़ूंगा नहीं किसी को। 10 हजार मांगते हो, शर्म आती है। कितना कमाते हैं, ये लोग। जाकर सबका पैसा वापस करना।

विधायक लक्ष्मी ध्रुव ने किया सीसी सड़क एवं रंगमंच निर्माण कार्य का भूमिपूजन

नगरी। सिहावा विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं उपाध्यक्ष मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकारण डॉ लक्ष्मी ध्रुव के मुख्य आतिथ्य में ग्राम पंचायत भीतररास के आश्रित ग्राम गढ़ियापरा में सी.सी.सड़क निर्माण कार्य का भुमिपूजन किया गया। ज्ञात हो कि विगत माह मे क्षेत्रीय विधायक डॉ लक्ष्मी ध्रुव के क्षेत्र भ्रमण के दौरान गढ़ियापारा निवासियों द्वारा विधायक महोदया के समक्ष प्रमुखता से अपनी मांग को रखे थे जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए विधायक निधि से सी.सी.सड़क निर्माण कार्य राशि 06.20 लाख रू. की स्वीकृति प्रदान की गई। जिसकी आज दिनांक 09.07.2023 का भूमिपूजन किया गया। साथ ही ग्राम झुंझराकसा में बहुप्रतिक्षित मांग रंगमंच राशि 03.50 लाख रू. का भूमिपूजन क्षेत्रीय विधायक के द्वारा किया गया।

झुंझराकसा में रंगमंच निर्माण के भूमिपूजन के दौरान उपस्थित ग्रामीणजनों द्वारा सामुदायिक भवन, सी.सी.रोड एवं मोबाईल टॉवर लगाने की मांग को प्रमुखता से रखा जिस पर विधायक महोदया द्वारा पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया। उक्त कार्यक्रम में रंजना सूर्यवंशी सरपंच ग्राम पंचायत भीतररास, विधायक प्रतिनिधि अख्तर खान, महेन्द्र धेनूसेवक उपाध्यक्ष कृषि उपज मंडी, दुर्गेश कश्यप उपाध्यक्ष ब्लाक कांग्रेस कमेटी बेलरगांव, एल.एल. ध्रुव पीसीसी सदस्य, अमृत लाल नाग वरिष्ठ कांग्रेसी, सुरेश नेताम, पंचगण एवं समस्त ग्रामवासी गढ़ियापारा, साथ ही ग्राम झुंझराकसा में कलेश्वरी मरकाम सरपंच ग्राम पंचायत झुंझराकसा, सविता कोड़ेपी पंच, शोभीराम नेताम सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी, आत्माराम मण्डावी, यशोदा नेताम पंच, अनिल कुंजाम पंच, जगदीश सामरथ, राकेश कोड़ोपी, शंकर लाल कुंजाम, आकाश नेताम, सहजाद मेमन, विनोद ध्रुव, आलोर सिंह मरकाम पंच, राजेन्द्र पुजारी, दुर्गेश समुन्द, मो. अयुब खान, एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।

रेललाइन पर लैंडस्लाइड होने की वजह से रेल यातायात पूरी तरह से ठप

एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन रद्द, भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के चलते के बस्तर को आंध्र प्रदेश के कोत्तावालसा से जोड़ने वाली केके रेल लाइन पर लैंडस्लाइड होने की वजह से रेल यातायात पूरी तरह से ठप हो गई है। बताया जा रहा है कि जगदलपुर से तकरीबन 250 किमी दूर अरकू रेल सेक्शन के पास बोर्राहलु और काराकवलसा इलाके में हुए भूस्खलन होने से रेल ट्रैक पर बोल्डर गिर गए हैं। इस वजह से इस लाइन पर रेल यातायात बाधित हो गया है।

हादसे की सूचना मिलने के बाद युद्धस्तर पर ट्रैक को ठीक करवाने का कार्य जारी है। डीआरएम पूरे कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रेलवे अफसरों के मुताबिक भारी बारिश नहीं हुई तो 24 घंटे में इस रूट को ठीक कर लिया जाएगा। इस रूट पर 4 यात्री ट्रेनों के अलावा 23 से अधिक मालगाड़ी गुजरती है।

हादसे के बाद मंगलवार को चलने वाली विशाखापटनम-कोरापुट पैसेंजर (08546) और कोरापुट-विशाखापटनम (08545) को निरस्त कर दिया गया है। 10 जुलाई की शाम किरंदुल से विशाखापट्टनम के लिए निकली नाइट एक्सप्रेस का रूट डायवर्ट किया गया। रेल यातायात बाधित होने की वजह से मालगाड़ियों का भी परिचालन बंद है। इससे लौह अयस्क का परिवहन भी बंद हो गया है। जिसकी वजह से एनडीएमसी को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा।

ईस्ट कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम रेल मंडल के डीआरएम अनूप सतपती से मिली जानकारी के मुताबिक अरकू रेलवे स्टेशन के नजदीक बोर्रागुहालु के बीच लैंड स्लाइड हुआ है। सोमवार देर शाम बड़ी-बड़ी चट्टानें टूटकर पटरी पर गिर गईं। हिल स्टेशन होने की वजह से बारिश के मौसम में हादसा होने का डर बना हुआ रहता है। जिसकी वजह से मार्ग बाधित हो गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद डीआरएम अनूप सतपती खुद एक्सीडेंट रिफिल ट्रेन लेकर मौके पर पहुंचे हैं। रात से ही मार्ग बहाल करने का काम किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

जगजीवन ने विजय बघेल को संयोजक बनने पर दी बधाई

बेमेतरा। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव नें घोषणा समिति के सदस्यों की सूची जारी कर दिया गया है जिसमे दुर्ग लोक सभा सांसद विजय बघेल को संयोजक बनाये गए हैज. विजय बघेल को संयोजक बनाये जाने पर नवागढ़ विधानसभा के भाजपा युवा नेता व अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष डॉ जगजीवन खरे नें दूरभाष के माध्यम से उनको बधाई एवं शुभकामनायें प्रेषित किये। साथ ही साथ आगामी चुनाव को लेकर नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के बारे मे गहन चर्चा भी किया गया, की किस तरीके से इस बार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ मे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है..और झूठा लबरा भूपेश सरकार को छत्तीसगढ़ से भगाना है इन बातों को लेकर चर्चा भी किया गया।

छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरूआत 17 से

कोरबा। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक 2023-24 का आयोजन हरेली त्योहार के दिन 17 जुलाई से शुरू किया जाएगा। छत्तीसढ़िया ओलंपिक 6 चरणों में लगभग ढ़ाई महीने तक आयोजित होगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल गतिविधियों को ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने, प्रतिभागियों को मंच प्रदान करने और उनमें खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा खेल भावना का विकास करने हेतु छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन किया जा रहा है। खेल विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हिस्सा ले सकेंगे। प्रतियोगिता में दलीय एवं एकल श्रेणी में 16 तरह के पारम्परिक खेलों को शामिल किया गया है। इस बार के ओलंपिक में एकल श्रेणी में रस्सीकूद एवं कुश्ती को भी जोड़ा गया है। आयोजन का दायित्व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय क्षेत्रों के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को सौंपा गया है।

एटीएम में पैसा डालने वाला ही निकला लूट का मास्टरमाइंड

बलौदाबाजार। हथबंद में एटीएम तोड़कर चोरी करने वाले 3 युवकों को हथबंद पुलिस ने सायबर सेल की मदद से 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की रकम 6 लाख 66 हजार 800 रुपये और घटना में प्रयुक्त बाइक को बरामद किया है। मामले का खुलासा करते हुए बलौदाबाजार पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने बताया कि, घटना महज 5 से 10 मिनट के अंदर हुई थी. एटीएम चोरी की घटना को गंभीरता से लिया और टीम बनाकर पूरी छानबीन करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया है. वहीं एटीएम से लूटी गई पूरी रकम बरामद कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने आगे बताया कि, घटना का प्रमुख आरोपी युवराज चंद्राकर है, जो एटीएम में पैसा डालने का काम करता है. जिसने अपने 2 साथी शुभम यादव और शुभम महावर को एटीएम लॉकर की चाबी और पासवर्ड बताया था. जिसके बाद दोनों आरोपियों ने एटीएम पहुंचकर लूट की वारदात को अंजाम दिया. लूट के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है।

मरीजों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए 6 बिस्तर अस्पताल का निर्माण

पाटन। तहसील मुख्यालय के अंतिम छोर व खारून नदी के तट पर बसे ग्राम तरीघाट जहां पर मरीजों के उत्तम व बेहतर स्वास्थ्य रखने के ख्याल से व ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा तरीघाट गांव में 6 विस्तर का अस्पताल स्वीकृति प्रदान किया गया है। मौजूद अस्पताल के जगह स्थल चयन के लिए बीएमओ आशिष वर्मा, इंजिनियर व ठेकेदार पहुंचे हुए थे, अधिकारियों को देख अतिक्रमण कारी एकत्र होने लगे व अतिक्रमणकारियों के बुलंद हौसले के चलते अस्पताल निर्माण नहीं होने के कारण अधिकारी सोमवार को बैरंग लौटे जिससे अस्पताल निर्माण संशय मे पढ़ गया। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पाटन विकासखंड के ग्राम तरीघाट मे 6 बिस्तर अस्पताल स्वीकृत किया गया है, जिसके चलते अस्पताल में हजारों लोगों का इलाज संभव हो पाएगा। ग्राम पंचायत तरीघाट मे उपस्वास्थ्य केंद्र पहले से ही मौजूद हैं, जिसके उपरांत लोगों को इलाज में परेशानी ना हो इसके लिए 6 बिस्तर अस्पताल निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

महापौर ने बस्तीवासियों से मिलकर जानी समस्याएं

कोरबा। महापौर राजकिशोर प्रसाद आज वार्ड क्र. 26 मुड़ापार बस्ती जनता के बीच पहुंचे। वहॉं के निवासियों ने मोहल्ला के एक स्थान से बरसाती पानी के निकासी संबंधी समस्या से महापौर को अवगत कराया। जिसे संज्ञान में लेते हुए महापौर ने निगम के स्वच्छता विभाग के अधिकारियों को इससे तत्काल अवगत कराया एवं मौके पर पहुचंकर स्वच्छता विभाग की टीम द्वारा वार्डवासियों ने जिन स्थानों पर पानी की निकासी बाधित होने की जानकारी दी थी, उन स्थानों पर पहुंचकर साफ-सफाई का कार्य कर बस्ती के पानी की निकासी संबंधी समस्याओं का तत्काल समाधान कराया। महापौर प्रसाद ने बस्ती वासियों से आग्रह किया कि नालियों में गंदगी, प्लास्टिक आदि न फेकें, उससे नालियो का पानी नहीं निकल पाता है और नालियो के जाम की स्थिति होने की संभावनाएॅं बन जाती है। बरसात का पानी निर्वाध गति से बहे, इस हेतु महापौर श्री प्रसाद ने बस्तीवासियों को समझाईश देते हुए उनसे सहयोग की अपेक्षा की।

क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है : ताम्रध्वज साहू

- **शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंडा में अटल टिंकरिंग लैब एवं लगभग 60 लाख की राशि से विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपुजन लोकार्पण**

अंडा। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंडा में अटल टिंकरिंग लैब एवं लगभग 60 लाख की राशि से विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपुजन लोकार्पण एवम् प्रतीभावान बच्चों का सम्मान समारोह कार्यक्रम गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के कर कमलों से संपन्न हुआ । इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू , अध्यक्षता देवेंद्र देशमुख अध्यक्ष जनपद पंचायत दुर्ग विषेश अतिथि नंद कुमार सेन अध्यक्ष केश कला बोर्ड , शशि सिन्हा महापौर नगर निगम रिसाली , जिला पंचायत सदस्य माया बेलचंदन, लक्ष्मी साहू जिला पंचायत सदस्य, रिवेंद यादव, देवेंद्र देशमुख अध्यक्ष जनपद पंचायत दुर्ग, मनीष चंद्राकर जनपद सदस्य, उमा देवी चंद्राकर सरपंच, पुकेश चंद्राकर अध्यक्ष शाला प्रबंधन एवं विकास समिति, जयराम चंद्राकर विधायक प्रतिनिधि , डीडी साहू , जेडी चेलक एसएमसी सदस्य, डीपी चंद्राकर, अन्य जनप्रतिनिधिगण, अतिथिगण , एल चंद्राकर प्रभारी प्राचार्य , पालकगण ग्रामवासी एवं शाला के समस्त स्टाफ व विद्यार्थी उपस्थित थे ।

कार्यक्रम में स्वागत भाषण अध्यक्ष जिला किसान कांग्रेस पुकेश चंद्राकार ने कहा की ग्राम अंडा में अब तक मंत्री जी द्वारा कोरोड़ो राशि से विकास कार्य हुआ है हमारी मांग के अनुसार लगातार ग्राम में सड़क ,सी सी सड़क निर्माण,भवन निर्माण , नाली निर्माण , स्वास्थ, शिक्षा के लिए कार्य हुआ है जिसके लिए मंत्री का आभार व्यक्त किया ।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ताम्रध्वज साहू ने कहा की क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। गांवों में मूलभूत सुविधाओं की ओर प्राथमिकता के साथ ध्यान दिया जा रहा है। गांवों के विकास में कोई कमी नहीं हुई है। पिछले साढ़े चार सालों में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीणों की मांग के अनुसार कार्य कराए गए हैं। उन्होनें आने वाले समय में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, अस्पताल, विश्राम गृह जैसे भवन निर्माण किया जायेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश सरकार के नेतृत्व में प्रदेश में किसानों की खुशहाली के लिए बनाई गई योजनाओं से खेती-किसानी की ओर लोगों का फिर से झुकाव हो रहा है।

इन कार्यों हुआ भूमिपूजन लोकार्पण

अटल लैब शा.उच्च.मा.शाला अंडा में 12.00 लाख कार्य , 6 बैड युनिट निर्माण कार्य प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र अण्डा - 9.6 लाख, .उच्च.मा शाला अंडा 3 रूम मरम्मत कार्य 5.12 लाख , पूर्व. मा.शाला अंडा 2 रूम मरम्मत कार्य 1.66 लाख रूपए, सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य 5.00 लाख रूपए, भूमिपूजन कार्य कर्मा भवन जीर्णोधार कार्य 2.91 लाख रूपए, शिव मंदिर जीर्णोधार कार्य 2.91 लाख रूपए, शीतला मंदिर जीर्णोधार कार्य 5.00 लाख रूपए,सार्वजनिक मंच निर्माण कार्य गुरुवार बाजार चौक 3.00 लाख रूपए, मुक्तिधाम शेड निर्माण कार्य 9.50 लाख रूपए की हैं।

गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के दिशा निर्देश मे नगर पालिका निगम रिसाली के वार्ड क्रमाक 17 के शीतला मंदिर समिति के पास भवन निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीसीसी महासचिव जितेन्द्र साहू थे। अध्यक्षता महापौर श्रीमती शशि अशोक सिन्हा ने की। इस अवसर पर प्रमुख रूप से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के महामंत्री चंद्रकांत कोरे महापौर परिषद के सदस्य गोविंद चतुर्वेदी चंद्रभान सिंह ठाकुर पार्षद श्रीमती गजेंद्री कोठारी आदि उपस्थित थे।

जनपद पंचायत उपाध्यक्ष व अन्य पर वित्तीय अनियमितता का आरोप

कोरबा। जनपद पंचायत कोरबा के उपाध्यक्ष व अन्य पर वित्तीय अनियमितता का गंभीर आरोप लगाया गया है। निर्माण कार्य पूर्ण कर प्रमाण पत्र जारी होने के बाद भी उसे अब भुगतान के लिए घुमाया जा रहा है। मामले की शिकायत कलेक्टर से की गई है। शासकीय धनराशि का गबन करने वालों की जांच कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। मामले की शिकायत रजगामार रोड इंडस्ट्रीय एरिया निवासी बेदराम चंद्राकर 30 वर्ष द्वारा की गई है।

शिकायत में कहा गया है कि शासन द्वारा ग्राम पंचायत श्यांग के जनपद पंचायत कोरबा में भारत भवन निर्माण कार्य वर्ष 2011-12 में राशि स्वीकृत किया था। उक्त कार्य को पूर्व में ग्राम पंचायत श्याग के सरपंच द्वारा किया गया थाए किन्तु यह कार्य अपूर्ण था। जिसको पूर्ण करने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोरबा जीके मिश्रा, जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 5 नंद कुमार कंवर, इंजीनियर संतोष नायक, ग्राम पंचायत सरपंच चरम सिंह राठिया, सचिव विनोद राठिया, रोजगार सहायक मुकेश कुमार सभी की सहमति व उनके कहने पर उसके द्वारा उक्त अपूर्ण निर्माण कार्य को 20 फरवरी 2021 से आरम्भ कर 15 फरवरी 2022 को पूर्ण कर लिया गया।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

आर्टिकल 370 मामले में दो अगस्त से होगी सुनवाई

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 2 अगस्त से सुनवाई करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत की पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने कहा कि याचिकाओं की सुनवाई सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर दैनिक आधार पर होगी। सुनवाई 2 अगस्त को सुबह 10:30 बजे शुरू होने वाली है। अदालत ने यह भी कहा कि पक्ष इस मामले पर 25 जुलाई तक अपने लिखित दस्तावेज जमा कर सकते हैं। पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय दो अगस्त से सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की सूची से अपना नाम हटाने के लिए आईएएस अधिकारी शाह फैसल द्वारा दिए गए आवेदन पर विचार की मंजूरी दी है।

कहां हैं मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी

नईदिल्ली। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हिंसा एक दूसरे का पर्याय बन गए हैं। राज्य में पंचायत चुनाव के नामांकन शुरू होने से लेकर अब तक करीब 45 लोगों की मौत हो चुकी है। पात्रा ने आरोप लगाया कि ये जितने लोग मारे गए हैं वह प्रायोजित है, यह एक पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या राज्य प्रायोजित है। इसमें पुलिस प्रशासन से लेकर जिला अधिकारी तक सम्मिलित हैं। उन्होंने कहा कि अगर यही दृश्य किसी भाजपा शासित राज्य से आ रहा होता तो हाहाकार मच गया होता। ये सारे नेता, जो हाथ पकड़-पकड़ कर राज्यों में खड़े होते हैं, कहां हैं ये सारे नेता? कहां हैं लालू प्रसाद यादव, कहां हैं नीतीश कुमार और कहां हैं मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी? उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी... इस पूरी व्यवस्था की, बंगाल में जिस प्रकार से लोगों की हत्या हो रही है, जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसकी तीव्र निंदा करती है।

एनसीपी टूटने पर भी शरद पवार और मजबूत होंगे : उमर

श्रीनगर। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी एकता की कवायद जारी है। इसी कड़ी में 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक होने जा रही है। हालांकि, इस बैठक से पहले विपक्ष को तब बड़ा झटका लगा जब महाराष्ट्र में एनसीपी दो गुटों में बंट गई है। इसे बड़ा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि यह शरद पवार के पार्टी है और वह विपक्ष के बड़े नेता हैं। इसको लेकर नेशनल कांफ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि एक पार्टी (एनसीपी) टूटी, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पार्टियां पहले भी टूटीं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस टूट गई, क्या उससे पहले विपक्ष की बैठक की जरूरत थी? ये लंबे समय से चलता आ रहा है, चलता रहेगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, तो मुझे नहीं लगता कि शरद पवार अपनी पार्टी टूटने के बाद कमजोर हुए हैं, मुझे लगता है कि वह और मजबूत हो गए हैं।

भाजपा ने उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का मांगा इस्तीफा

पटना। भाजपा ने 'नौकरी के बदले जमीन' लेने संबंधी घोटाले में तेजस्वी के खिलाफ सीबीआई के आरोप पत्र दायर किये जाने के मद्देनजर उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जिस मंत्री के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा रहा है वह कैबिनेट का हिस्सा नहीं हो सकता। यह एक रस्म रही है जब बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और अन्य मंत्रियों को एक एफआईआर के बाद कैबिनेट से हटा दिया गया था, तो कैबिनेट में बैठे इन मंत्रियों (तेजस्वी यादव) पर आरोप पत्र दायर किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों के साथ सरकार चलाना बिल्कुल गलत है। यह जनता के साथ धोखा है और हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कैबिनेट के अंदर और बाहर भी हम विधानसभा को भ्रष्ट मंत्रियों को बर्खास्त करने के लिए मजबूर करेंगे।

देश और महाराष्ट्र की राजनीति निचले स्तर पर : उद्धव ठाकर

मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भारत में राजनीति अब आईपीएल की तरह हो गई है और कोई नहीं जानता कि कौन किस तरफ से खेल रहा है। मीडिया को संबोधित करते हुए शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) का नेतृत्व कर रहे उद्धव ने कहा कि ठाकरे देश और महाराष्ट्र में राजनीति का स्तर निचले स्तर पर पहुंच गया है। लोग परेशान हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं जहां भी गया, मुझे यही तस्वीर दिखी। कोई काम नहीं हुआ, कोई योजनाएं जनता तक नहीं पहुंचीं। उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य और केंद्र में हो रही राजनीति को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। तो अब सोचने का समय है - क्या ये योजनाएँ लोगों तक पहुँच रही हैं या नहीं? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार अभी भी जनता के सवालों पर ध्यान देती नजर नहीं आ रही है।

ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ाना अवैध : सुप्रीम कोर्ट

■ शीर्ष कोर्ट से केंद्र को झटका

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को करारा झटका लगा है। शीर्ष कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को अवैध ठहरा दिया है। शीर्ष अदालत ने उन्हें अपने लंबित काम निपटाने के लिए 31 जुलाई 2023 तक का समय दिया है। साथ ही न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने ईडी निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम पांच साल तक बढ़ाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में संशोधन की बात कही है। अदालत ने कहा है कि सरकार कानून बनाकर कार्यकाल में विस्तार कर सकती है, लेकिन अध्यादेश लाकर ऐसा करना वैध नहीं है।

2018 में संजय कुमार मिश्रा की हुई थी नियुक्ति

गौरतलब है कि संजय कुमार मिश्रा को नवंबर 2018 में प्रवर्तन निदेशालय के पूर्णकालिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। संजय मिश्रा 1984-बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) आयकर कैडर के अधिकारी हैं। उन्हें पहले जांच एजेंसी में प्रमुख विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। ईडी में नियुक्ति से पहले संजय मिश्रा दिल्ली में आयकर विभाग के मुख्य आयुक्त के रूप में कार्यरत थे।

प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के कार्यकाल के विस्तार को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इनमें उनके सेवा विस्तार को अवैध ठहराया गया था। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने आठ मई को प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के कार्यकाल के विस्तार को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस बीआर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।

आठ मई को हुई सुनवाई के दौरान, केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को अवगत कराया कि एसके मिश्रा पुलिस महानिदेशक नहीं हैं, लेकिन वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए, संसद ने सचेत रूप से फैसला लिया। मेहता ने अदालत को यह भी बताया था कि एसके मिश्रा नवंबर से सेवानिवृत्त होंगे। दरअसल, कोर्ट 17 नवंबर 2022 को केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी,

जिसमें सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक एसके मिश्रा का तीसरा कार्यकाल बढ़ाया था।

आठ मई की सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा को दिए तीसरे सेवा विस्तार पर केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या वह इतने जरूरी हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद उनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने पूछा था क्या कोई व्यक्ति इतना जरूरी हो सकता है। शीर्ष अदालत ने 2021 के अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि सेवानिवृत्ति की उम्र के बाद प्रवर्तन निदेशक के पद पर रहने वाले अधिकारियों का कोई भी सेवा विस्तार कम अवधि का होना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया था कि संजय मिश्रा को आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने उठाए थे सवाल

जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की पीठ के समक्ष केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि मिश्रा का विस्तार प्रशासनिक कारणों से आवश्यक था और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के भारत के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण था। इस पर पीठ ने सवालों की झड़ी लगाते हुए पूछा था कि क्या ईडी में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो उनका काम कर सके? क्या एक व्यक्ति इतना जरूरी हो सकता है? आप के मुताबिक ईडी में कोई और सक्षम व्यक्ति है ही नहीं? 2023 के बाद इस पद का क्या होगा जब मिश्रा सेवानिवृत्त हो जाएंगे?

केंद्र का तर्क, भारत की रेटिंग नीचे न जाए इसलिए जरूरी

तुषार मेहता ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग पर भारत के कानून की अगली सहकर्मी समीक्षा 2023 में होनी है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत की रेटिंग नीचे नहीं जाए, प्रवर्तन निदेशालय में नेतृत्व की निरंतरता महत्वपूर्ण है। मिश्रा लगातार कार्यबल से बात कर रहे हैं और इस काम के लिए वह सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। कोई भी बेहद जरूरी नहीं है लेकिन ऐसे मामलों में निरंतरता जरूरी है।

कार्यकाल विस्तार पर रोक का विपक्षी नेताओं ने किया स्वागत

सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के तीसरे कार्यकाल को रद्द करने का विपक्षी नेताओं ने स्वागत किया है। साथ ही शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे एजेंसी का दुरुपयोग करने वालों के चेहरे पर तमाचा बताया। चतुर्वेदी ने कार्यकाल के विस्तार को अवैध बताते हुए मिश्रा द्वारा लिए गए सभी निर्णयों की जांच की भी मांग की। चतुर्वेदी ने अपने ट्वीट में कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्कृष्ट निर्णय। उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो अधिकार का दुरुपयोग कर रहे थे और अवैध कार्यकाल विस्तार के माध्यम से आतंक और चरित्र हनन का माहौल बनाया था। इसके साथ ही उद्धव गुट की नेता ने कहा कि साथ ही अगर ईडी निदेशक का एक्सटेंशन अवैध है तो उनके और उनकी टीम द्वारा लिए गए सभी फैसलों की जांच की जानी चाहिए अन्यथा उन्हें भी अवैध माना जाएगा। इस चुभने वाले फैसले के बाद क्या ईडी निदेशक के पास महीने के अंत तक पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार है? मिश्रा के विस्तार को याचिकाओं के एक समूह द्वारा चुनौती दी गई थी, जो शीर्ष अदालत के सितंबर 2021 के आदेश पर आधारित थी। याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, जया ठाकुर और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा समेत अन्य शामिल हैं। लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा ने मिश्रा के सेवा विस्तार को अवैध करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपा- हम आपसे चुनाव में लड़ेंगे, हम आपसे अदालत में लड़ेंगे। हम खेतों और सड़कों पर लड़ेंगे, हम कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे।

कांग्रेस अध्यक्ष ने विपक्षी दलों के नेताओं को लिखा पत्र

खड़गे ने बेंगलुरु में बैठक के लिए विपक्ष को किया आमंत्रित

नईदिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली अगली एकता बैठक में भाग लेने के लिए शीर्ष विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने शीर्ष विपक्षी दल के नेताओं को संबोधित एक पत्र में उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई 23 जून को पटना में आयोजित विपक्षी बैठक में उनकी भागीदारी के बारे में याद दिलाया। अपने पत्र में खड़गे ने लिखा कि बैठक एक बड़ी सफलता थी क्योंकि हम विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की और एक साथ चुनाव लड़ने पर सहमत हुए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हम विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने में सक्षम हुए जो हमारी लोकतांत्रिक राजनीति को खतरे में डालते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने नेताओं को आगे याद दिलाया कि हम जुलाई में फिर से मिलने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना ??है कि इन चर्चाओं को जारी रखना और हमने जो गति बनाई है उसे आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण है। हमारा देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, उनका समाधान खोजने के लिए, हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। इसके अलावा, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया 17 जुलाई को शाम 6.00 बजे बेंगलुरु में होने वाली बैठक और उसके बाद रात्रिभोज में भाग लेना सुनिश्चित करें। बैठक 18 जुलाई 2023 को सुबह 11.00 बजे से जारी रहेगी। बेंगलुरु में आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूं।

कई नए दल भी हो सकते हैं शामिल

2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष की पहली बैठक पटना में हुई, जिसमें 15 से ज्यादा पार्टियां शामिल हुईं। बैठक में शामिल होने वालों में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राकांपा प्रमुख शरद पवार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन समेत कई नेता शामिल थे। यह बैठक आगामी 2024 के आम चुनावों में भाजपा को हराने के लिए विपक्ष की रणनीति तैयार करने के लिए हो रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई नए दल भी इस बार शामिल हो सकते हैं जो पटना में साथ नहीं थे।

बृजभूषण का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरा

नई दिल्ली। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया गया, भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट सामने आ गई है। हैरानी की बात है कि इतना कुछ होने के बाद भी प्रधानमंत्री चुप हैं। इस मामले में हमारे पीएम मोदी से कुछ सवाल- पीएम मोदी, महिला पहलवानों से जुड़े इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं? अपने इस चहेते सांसद को पार्टी से कब बाहर करेंगे? भाजपा सांसद बृजभूषण की गिरफ्तारी कब होगी? आपकी सरकार बृजभूषण को संरक्षण देना कब बंद करेगी?

खेल
प्रमुख समाचार

दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र के बीच आज खिताबी मुकाबला

नईदिल्ली। दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र के खिलाड़ी बुधवार से शुरू हो रहे दलीप ट्रॉफी फाइनल में एक दूसरे का सामना करेंगे तो नजरें खिताब जीतने के साथ व्यक्तिगत स्तर पर भी कुछ लक्ष्य हासिल करने पर लगी होंगी। टीम के नजरिये से देखें तो पश्चिम ने दलीप ट्रॉफी फाइनल खेलकर 19 में जीत दर्ज की है। वह इस टूर्नामेंट की सबसे कामयाब टीम है जबकि दक्षिण ने 14 बार खिताब जीता है और वह पश्चिम का दबदबा कम करना चाहेगा। पिछले साल फाइनल में दक्षिण को अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली पश्चिम क्षेत्र टीम ने 294 रन से हराया था। दलीप ट्रॉफी के जरिये कुछ खिलाड़ी व्यक्तिगत लक्ष्य भी हासिल करना चाहेंगे और चेतेश्वर पुजारा इसका उदाहरण हैं। खराब फॉर्म के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम से बाहर किये गए पुजारा अपनी उपयोगिता फिर साबित करने को लालायित होंगे। विहारी ने आखिरी बार भारत के लिये 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम टेस्ट में खेला था जबकि सुंदर ने इस साल की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ सफेद गेंद की श्रृंखला खेली थी। चोटों और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण उन्हें आगे मौके नहीं मिल सके लेकिन अब वे चयन का दावा पुख्ता करना चाहेंगे।

दक्षिण क्षेत्र- हनुमा विहारी (कप्तान), मयंक अग्रवाल, साइ सुदर्शन, रिकी भुई, आर समर्थ, वाशिंगटन सुंदर, सचिन बेबी, प्रदोष रंजन पॉल, साइ किशोर, वी कावेरप्पा, वी विशाख, केवी शशिकांत, दर्शन मिसाल, एन तिलक वर्मा।

पश्चिम क्षेत्र- प्रियांक पांचाल (कप्तान), चेतेश्वर पुजारा, सूर्यकुमार यादव, हार्विक देसाई, पृथ्वी साव, हेत पटेल, सरफराज खान, अर्पित वासवडा, अतीत सेठ, शम्स मुलानी, केदार जाधव, धर्मेंदसिंह जडेजा, तुषार देशपांडे, चिंतन गाजा, अर्जन नागवासवाला।

मैच का समय- सुबह 9 .30 से।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/ प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 274 अंक चढ़ा, निफ्टी 19450 करीब हुआ बंद

मुंबई। स्थानीय शेयर बाजारों में तेजी का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा और बीएसई सेंसेक्स लगभग 274 अंक चढ़ गया। वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख और विदेशी पूंजी प्रवाह जारी रहने से बाजार बढ़त में रहा। सूचकांक में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस और आईटीसी के शेयरों में लिवाली से बाजार में तेजी कायम रही। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 273.67 अंक यानी 0.42 प्रतिशत की बढ़त के साथ 65,617.84 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 526.42 अंक उछलकर 65,870.59 अंक तक चला गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 83.50 अंक यानी 0.43 प्रतिशत की बढ़त के साथ 19,439.40 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में सन फार्मा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, आईटीसी, नेस्ले, लार्सन एंड टुब्रो, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, टाइटन प्रमुख रूप से लाभ में रहे।

सुजलॉन को मिला विंड पावर प्रोजेक्ट का ठेका

नईदिल्ली। अक्षय ऊर्जा समाधान प्रदाता सुजलॉन समूह को गुजरात में केपी ग्रुप से 47.6 मेगावॉट की पवन ऊर्जा परियोजना का ठेका मिला है। हालांकि, कंपनी ने सौदे के मूल्य का खुलासा नहीं किया है। यह परियोजना भड़्च जिले के वागरा में स्थित है। कंपनी ने बयान में कहा कि इस परियोजना के 2024 में चालू होने की उम्मीद है। इस आकार की परियोजना 36,000 घरों को रोशन कर सकती है और सालाना कार्बन उत्सर्जन में 1.42 लाख टन की कमी ला सकती है। सुजलॉन ग्रुप परियोजना के लिए एस133 पवन टर्बाइन की आपूर्ति करेगी और परियोजना के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी। साथ ही वह परियोजना को चालू भी करेगी। सुजलॉन ग्रुप के सीईओ जे पी चलसानी ने कहा, ''इस परियोजना से उत्पादित बिजली को आपूर्ति वाणिज्यिक और औद्योगिक (सीएंडआई) उपभोक्ता खंड को की जाएगी।''

भारत में चिप बनाने अलग से आवेदन करेगी फॉक्सकॉन

नईदिल्ली। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण कंपनी फॉक्सकॉन की भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई लगाने के लिए अलग से आवेदन करने की योजना है। कंपनी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। कंपनी ने बयान में कहा कि वह सेमीकंडक्टर के संशोधित कार्यक्रम और डिस्प्ले फैब पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवेदन करने पर काम कर रही है। ''हम इसके लिए अधिक अनुकूल भागीदार चाहते हैं।'' फॉक्सकॉन ने सोमवार को वेदांता के साथ सेमीकंडक्टर संयुक्त उद्यम से बाहर निकलने की घोषणा की थी। फॉक्सकॉन ने कहा था कि वह खनन क्षेत्र के दिग्गज उद्योगपति अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली वेदांता लि. के साथ 19.5 अरब डॉलर के संयुक्त उद्यम से बाहर निकल रही है।

मिंडा कॉर्पोरेशन को मिला ईवी बैटरी चार्जर का ऑर्डर

नईदिल्ली। वाहन कलपुर्जा कंपनी मिंडा कॉरपोरेशन को एक प्रमुख वाहन विनिर्माता से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी चार्जर बनाने का 750 करोड़ रुपये का ठेका मिला है। मिंडा कॉरपोरेशन ने मंगलवार को शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि इस उत्पाद का विनिर्माण पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी स्पार्क मिंडा ग्रीन मोबिलिटी सिस्टम्स के पुणे संयंत्र में किया जाएगा। मिंडा ने यह नहीं बताया है कि उसे यह ऑर्डर किस वाहन कंपनी से मिला है। मिंडा कॉरपोरेशन के कार्यकारी निदेशक आकाश मिंडा ने कहा, ''यह ऑर्डर स्पार्क मिंडा के ईवी उत्पाद पोर्टफोलियो के प्रति ग्राहकों के भरोसे को दर्शाता है।'' कंपनी ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में उसे मिले कुल ऑर्डर में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत थी।

निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल, भारतीय अर्थव्यवस्था जल्द हो सकती है गुलाबी

सतीश सिंह

मौजूदा समय में अमेरिका सहित लगभग तमाम विकसित देशों के शेयर बाजार में बिकवाली का दौर जारी है। उतार-चढ़ाव के साथ-साथ शेयर बाजार गोते भी लगा रहा है। कोरोना महामारी, भू-राजनीतिक संकट, रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमत की वजह से विकसित देशों में शेयर बाजार की हालत खस्ता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी नरमी बनी हुई है। कुछ देशों में मंदी आने के आसार बने हुए हैं।

इसके ठीक उलट भारतीय शेयर बाजार में विगत कुछ महीनों से उछाल की स्थिति बनी हुई है। चार जुलाई को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का सेंसेक्स 274 अंकों की बढ़त के साथ 65,479 पर बंद हुआ। बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर्व, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की लिवाली से सेंसेक्स में उछाल की स्थिति बनी हुई थी। अपने शुरुआती कारोबार में बीएसई 381.55 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 65,586.60 अंकों के स्तर पर पहुंच गया। इसके पहले 21 जून को यह 261 अंकों की बढ़त के साथ 63,588 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ था।

जानकारों के अनुसार, इस साल के अंत तक सेंसेक्स 70,000 के स्तर पर पहुंच सकता है। शेयर बाजार जिस गति से आगे बढ़ रहा है, उससे इस अनुमान में कोई अतिश्योक्ति नहीं दिखती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) या निफ्टी 28 जून को 19,000 के स्तर को पार कर गया। चार जुलाई को यह 90.95 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 19,413.50 अंकों पर पहुंच गया। जानकारों के अनुसार, निफ्टी इस साल के अंत तक 21,000 के स्तर पर पहुंच सकता है।

शेयर बाजार में लगातार उछाल की स्थिति बने रहने की वजह से पिछले तीन महीनों में शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति में 40 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है। शेयर बाजार में उछाल का कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) द्वारा ज्यादा निवेश करना है। इसमें अमेरिका और यूरोप के निवेशकों की संख्या अधिक है। जून में विदेशी निवेशकों ने भारत में 47 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया था। इससे चीन की परेशानी बढ़ रही है, क्योंकि चीन का बाजार कम निवेश होने से ठंडा पड़ता जा रहा है। विदेशी निवेशक चीन के बाजार से लगातार पैसा निकाल रहे हैं, जिसका कारण चीन का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों का नरम तथा निर्माण एवं विनिर्माण क्षेत्र का सुस्त रहना है। इसके कारण चीन की अर्थव्यवस्था पहले से कुछ कमजोर हो गई है। चीन में इस साल जनवरी और फरवरी में विदेशी निवेशकों ने अच्छा-खासा निवेश किया था, लेकिन बाद के महीनों में निवेशकों ने 34 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि निकाल ली।

अभी विदेशी निवेशक चीन की जगह भारत में निवेश करना बेहतर मान रहे हैं, क्योंकि फिलहाल, भारत की अर्थव्यवस्था चीन से अधिक मजबूत है। विदेशी निवेशक तो इसका फायदा उठा ही रहे हैं, घरेलू निवेशक भी इसका फायदा उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, वर्ष 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था के 30 खरब डॉलर से 50 खरब डॉलर होने की बात कही जा रही है। एचएसबीसी की हालिया रिपोर्ट में तो भारतीय अर्थव्यवस्था के पांच से दस वर्षों में 70 खरब डॉलर होने की बात कही गई है।

कोई निवेशक शेयर बाजार में निवेश करना चाहता है, तो उसे सतर्क और शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों की हरकतों पर पैनी नजर रखने की जरूरत है। शेयर की कीमत में उतार-चढ़ाव से सिर्फ निवेशकों को नुकसान नहीं होता है, इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। हालांकि, अभी शेयर बाजार में निवेश का अनुकूल माहौल है, जिसका फायदा सभी देसी एवं विदेशी निवेशकों को उठाना चाहिए। अधिक निवेश से भारतीय अर्थव्यवस्था जल्द से जल्द गुलाबी हो सकती है।

पार्टी की टूट नहीं रोक पाए शरद पवार

शशिधर पाठक

शरद पवार में आस्था रखने वाले एनसीपी के नेता इस बात से हैरान हैं कि टूट की आशंका के बाद भी इसे रोकने के लिए शरद पवार ने ठोस प्रयास क्यों नहीं किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अपने भाई श्रीनिवास पवार के पास पहुंचे। उनसे चर्चा की। इसे महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहे अंदरखाने के प्रयास से जोड़कर देखा जा रहा है। श्रीनिवास पवार से अजीत पवार की चर्चा के बाद उनके बेटे युगेन्द्र पवार एनसीपी प्रमुख शरद पवार के पास आए। वहां उनकी मुलाकात अपने दादा शरद पवार और बुआ सुप्रिया सुले से हुई। गौरतलब है कि शरद पवार को छोड़कर अजीत पवार के साथ जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल ने भी सीनियर पवार पर बड़ा ताना मारा था। छगन भुजबल शरद पवार के नासिक (येवला) आने से चकित थे और खुद के द्वारा धोखा देने के आरोपों को खारिज करते हुए इसे शरद पवार के परिवार में फूट बताया था। ऐसे में इसके भी कयास लग रहे हैं कि पवार परिवार और खासकर श्रीनिवास पवार परिवार कहीं कोई बीच की कड़ी तो नहीं जोड़ रहे हैं। दरअसल पवार परिवार को पता है कि इस बिखराव का आने वाले समय में नतीजा क्या होगा? शरद पवार महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। इससे एनसीपी को छोड़कर गए विधायकों में भी खलबली है। छह-सात महीने बाद राज्य में विधानसभा चुनाव है। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि किसके साथ कितने विधायक हैं? यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आगामी चुनाव में कौन कितने विधायकों को जितवा सकता है। यह क्षमता शरद पवार के पास है। देशमुख कहते हैं कि भाजपा के पास विधायकों की संख्या नहीं है। 2019 से लगातार तोड़-फोड़ में लगी है। पहले 2019 में यह प्रयास किया था। इसके बाद पिछले डेढ़-दो साल से इसी में लगी थी। इसे राज्य की जनता पसंद नहीं कर रही है। उसे आगामी चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शरद पवार दशकों से महाराष्ट्र की राजनीति के एक अहम किरदार रहे हैं। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि उनकी राजनीति को समझना बहुत आसान नहीं है। अपनी इन्हीं विलक्षण क्षमताओं के जरिए उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में कई बार चौंकाया। तीन बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे तो देश के रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री भी रहे। पवार ने जून 1999 में भी चौंकाया था, जब उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी की स्थापना की। एनसीपी को खड़ा किया। दिलचस्प है कि पवार की एनसीपी में लगभग सभी बड़े नेता चाहे वह प्रफुल्ल पटेल हों या छगन भुजबल या फिर अन्य, सभी कारोबारी पृष्ठभूमि से हैं। सीनियर पवार ने इन्हें खूब आगे भी बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर छगन भुजबल। छगन भुजबल को भ्रष्टाचार के आरोप में एक से अधिक बार अपना पद छोड़ना पड़ा। तेलगी स्टांप घोटाले का भी आरोप भुजबल पर लगा था। लेकिन पवार ने कभी इसकी परवाह नहीं की। शरद पवार उन्हें शिवसेना से तोड़ लाए थे। शरद पवार ने उन्हें कई बार राज्य का उप मुख्यमंत्री बनवाया। इसी तरह से प्रफुल्ल पटेल की एनसीपी में राष्ट्रीय हैसियत को अपने बाद और दूसरे नंबर की बनाए रखा। भतीजे अजीत पवार को आगे बढ़ाया। इनकी तुलना में उनका ध्यान पुत्री सुप्रिया सुले की तरफ कम था। शरद के खेमे के नेता कहते हैं कि भाऊ (शरद) को उम्मीद नहीं थी कि लोग (छगन, प्रफुल्ल, दिलीप विलसे पाटिल) इस हद तक चले जाएंगे।

समान संहिता के पक्षधर थे डॉ. अंबेडकर

रमेश शर्मा

समान नागरिक आचार संहिता की चर्चा आरंभ होते ही कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा एक बार फिर मुसलमानों को भ्रमित कर साम्प्रदायिकता फैलाने का प्रयास किया जाने लगा ताकि भारत में यह साम्प्रदायिक विभाजन की रेखा बनी रहे । इस अभियान को कुछ ऐसे राजनीतिक दल भी हवा देने लगे जिन्हे अपनी सत्ता के सूत्र केवल जाति और धर्म की विभाजन रेखाओं में ही दिखाई देते हैं।

कट्टरपंथियों द्वारा साम्प्रदायिक आधार पर सामूहिक हिंसा और विध्वंस करने का एक लंबा इतिहास है । यदि हम बहुत पुरानी बात न करें और केवल पिछले सौ वर्षों में इतिहास के पन्ने पलटें तो मालाबार हिंसा से लेकर मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन और भारत विभाजन की त्रासदी तक ही लाखों बेगुनाहों की मौत और करोड़ों के बेघरबार होने का वितरण भरा पड़ा है । उसके बाद भी धार्मिक आधार पर खींची जाने वाली विभाजन रेखा बनाये रखने का न संघर्ष रुका और न विचार बदला। आशा की गई थी कि शेष भारत में इन त्रासदियों से सबक लेकर सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे। सबके अपनी एक धार्मिक पसंद हो सकती है, धार्मिक आचार विचार अपनाने का अधिकार होगा पर यह उनका निजीत्व ही होगा । एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में सबके समान अधिकार और कर्तव्य हों जैसा दुनियाँ के दूसरे देशों में है । इस सिद्धांत तो समय समय पर अनेक राष्ट्रनायकों ने दोहराया है और यही बात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रमोदी ने दोहराई। निसंदेह यह बात सही है कि यदि एक ही परिवार के दो व्यक्तियों के अधिकार अलग-अलग होंगे तो यह उस परिवार में परस्पर ईष्या द्वेष और तनाव का कारण बनेगा। सबको समान अवसर मिलें, सबके समान अधिकार हों तभी समाज समरूप रहेगा और परिवार प्रगति करेगा । यही सिद्धांत किसी देश के सभी नागरिक के अधिकारों पर भी लागू होना चाहिए। इसलिए भारत में समान नागरिक संहिता लागू होना आवश्यक है । देश में सभी के नागरिक अधिकार समान होने के ऐसे विचार लगभग उन सभी राजनेताओं के रहे हैं जो राजनीति का लक्ष्य राष्ट्र सेवा मानते हैं। हाँ बाँटो और राज्य करों के अंग्रेजों के सिद्धांत पर चलते हुये जो राजनीति को केवल सत्ता प्राप्त करने का एक माध्यम बनाये रखना चाहते हैं उनके विचार भिन्न हैं। विचारों की यह भिन्नता संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होने के पहले दिन से देखी जा रही है और आज भी है । देश सबके नागरिक अधिकार समान होनै का विषय तब भी आया था जब संविधान का निर्माण हो रहा था । संविधान सभा के अधिकांश सदस्य समान नागरिक आचार संहिता के पक्ष में थे

। किंतु कुछ लोग धार्मिक आधार पर विभाजन के उन कानूनों को स्वतंत्र भारत के संविधान में भी बनाये रखना चाहते थे जो स्वतंत्रता के पहले अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर बनाये थे । जो लोग धर्म या जाति आधारित विशिष्ट अधिकार देने की बात कर रहे थे । तब संविधान प्रारूप तैयार करने की समिति के अध्यक्ष डाक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत स्पष्ट कहा था कि-

मैं व्यक्तिगत रूप से समझ नहीं पा रहा हूं कि किसी धर्म (मजहब) को यह विशाल, व्यापक क्षेत्राधिकार क्यों दिया जाना चाहिए। ऐसे में तो धर्म, जीवन के प्रत्येक पक्ष पर हस्तक्षेप करेगा और विधायिका को उस क्षेत्र पर अतिक्रमण से रोकेगा। यह स्वतंत्रता हमें क्या करने के लिये मिली है? हमारी सामाजिक व्यवस्था असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी है। यह स्वतंत्रता हमे इसलिये मिली है कि हम इस सामाजिक व्यवस्था में जहाँ हमारे मौलिक अधिकारों के साथ विरोध है वहाँ वहाँ सुधार कर सकें।

उनके शब्दों में तीन बातें बहुत स्पष्ट हैं कि वे किसी को धर्म आधारित विशेषाधिकार देने के पक्ष में नहीं थे । वे सबको समान अधिकार देने के पक्ष में थे । और तीसरी बात कि कोई विशिष्ट प्रावधान रखने को कह रहा होगा जिस पर उन्होंने कहा कि- मैं समझ नहीं पा रहा इन शब्दों से बहुत स्पष्ट है कि कोई अदृश्य शक्ति ऐसी थी जो इन प्रावधानों को लागू करने पर जोर दे रही थी। और वह इतनी सशक्त थी कि धार्मिक अलगाव के सभी प्रावधान लागू हो गये। कहने के लिये हम गर्व करते हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहब हैं पर उनकी मंशा और विचारों के विपरीत धार्मिक आधार पर कुछ समूहों के विशेषाधिकार देने का यह प्रावधान कैसे सम्मिलित हुये यह अपने आप में आश्चर्यजनक है। वह भी इतनी होशियारी के साथ कि अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मुसलमान और ईसाई पंथ के अनुयाइयों को हैं वे अधिकार हिन्दु अल्पसंख्यक वाले प्रातों में हिन्दुओं को नहीं है। उन प्रातों में बहुसंख्यक होने के बावजूद मुसलमानों और ईसाईयों को ही हैं। यह इन प्रावधानों में मुसलमानों और इसाइयों के लिए किये विशेषाधिकार के कारण है। सरकार भारत में मुसलमानों और ईसाईयों को विशेषाधिकार तो देती है पर उनके निजीत्व में हस्तक्षेप नहीं कर सकती । इसकी व्याख्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करता है। यह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और शरीयत आधारित यह मुस्लिम पर्सनल लॉ कोई बहुत पुराना नहीं है । इसकी नींव 1937 में पड़ी थी और 1939 से लागू हुआ। बाबा साहब समेत संविधान सभा के अधिकांश सदस्य इस कानून को अंग्रेजों के साथ ही विदा करना चाहते थे कि ताकि लाखों बलिदानों से मिली स्वंतंत्रता को सहेजा जा सके किन्तु अलगाव के यह प्रावधान ज्यों के त्यों बने रहे जिनका उपयोग करके कुछ कट्टरपंथी भारत का सामाजिक वातावरण बिगाड़ने का प्रयास करते हैं और आज भी कर रहे हैं।

अलग-अलग धर्मों के अलग कानून होने से केवल सामाजिक विभाजन की रेखा ही गहरी नहीं होती अपितु इससे प्रशासनिक और न्यायपालिका की कार्यशैली पर भी बोझ पड़ता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से यह परेशानी दूर होगी और न्यायालयों में लंबित पड़े प्रकरणों के निबटारे में गति आयेगी । सभी के लिए समान कानून होने से अनेक प्रकार के विभाजनकारी षड्यंत्र न हो सकेंगे जो अक्सर देखे जा रहे हैं।

आज भारत की प्रगति की दिशा को पूरा संसार आश्चर्यजनक तरीके से देख रहा है। शैक्षणिक, आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण से भारत की गति अनूठी है जिसे विश्व की कुछ शक्तियाँ कमजोर करना चाहती हैं। वे नित नये षड्यंत्र रच रहीं हैं। भारत की इस विकास गति को अवरुद्ध करने केलिये उन्हे केवल साम्प्रदायिक विभाजन का हथियार अनूठा लगता है जिसे वे कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथ में थमा देते हैं। भारतीय समाज में अशान्ति उत्पन्न होती है और सरकार अपनी विकास गति से ध्यान हटाकर विधि व्यवस्था बनाने के काम में लगती है । इसलिए इस समस्या का एक मात्र समाधान एक नागरिक आचार संहिता ही है। जिसके विरोध के लिये विदेशी कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी सामने आये। वे मुस्लिम समुदाय को भ्रमित कर रहे हैं। उनके धार्मिक अधिकार और पहचान खत्म होने का कुप्रचार कर रहे हैं। जबकि समान नागरिक आचार संहिता में किसी के धार्मिक विश्वास और पहचान प्रभावित नहीं होगी। यह आचार संहिता तो भारत में समरसता और समानता का वातावरण बनाने के लिये है, सामाजिक एकता बढ़ाने के लिये है। यदि देश के नागरिकों में किसी को धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होंगे। सबको समान अधिकार होगे तो इससे सबके बीच सामाजिक एकता ही तो बढ़ेगी । परस्पर ईष्या और वैमनस्य का भाव समाप्त होगा। जो देश की विकासगति को और तीव्र करेगी। हाँ देश में सभी भारतीयों के एक समान कानून लागू होने से दो प्रकार की शक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा। एक तो उन कट्टरपंथियों पर जो कुछ विदेशी षड्यंत्रों के तहत भारतीय समाज में विभेद पैदा करने के ठेकेदार हैं और दूसरे उन राजनीतिक दलों पर जिनकी राजनीति केवल जाति और धर्म के विभाजन के आधार पर चलती है। वे धार्मिक आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण नहीं कर सकेंगे। संविधान की भावना भी समान नागरिक आचार संहिता की है और इसी आधार पर शाहबानू प्रकरण पर अदालत का निर्णय आया था। यह बात अलग है कि तब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शाहबानो प्रकरण में दिये गए निर्णय को तात्कालीन सरकार ने संसद में संशोधन प्रस्ताव के माध्यम से पलट दिया था। यदि समान नागरिक संहिता लागू होती है तो इससे महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आएगा। जिन धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। उनमें सुधार होगा। इन धार्मिक वर्ग की महिलाओं को भी अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और बच्चों को गोद लेने के नियमों में भी सुधार होगा।

आज संसार कहाँ जा रहा है। विज्ञान ने आर्टिफिशल इंटेलिजेंस जैसे नागरिक खोज रहा है और दूसरी ओर कुछ इस्लामिक कट्टपंथी अपने समाज को कहाँ तक सीमित रखना चाहते हैं। यह इन कट्टरपंथियों का कारण है कि बंगलादेश और पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर किन्तु भारत के मुसलमान प्रगति कर रहे हैं। यदि समान नागरिक आचार संहिता लागू होती है तो इसका सबसे अधिक लाभ पूरे मुस्लिम समुदाय को होगा। लेकिन कट्टपंथियों की दुकाने जरूर कमजोर होगी इसीलिए वे समाज को भ्रमित कर विरोध का वातावरण बना रहे हैं।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद् (भाग-4)

गतांक से आगे...

इस जगत् के अनृत (मिथ्या) स्वरूप को भली-भाँति समझ लेना ही प्राणायाम कहा गया है। चित्त का अन्तर्मुखी भाव ही प्रत्याहार कहलाता है। चित्त का निश्चल (अचल) भाव धारण कर लेना ही धारणा है। मैं चिन्मात्र स्वरूप हूँ, यही चिन्तन (भाव) ध्यान कहा गया है।

ध्यान का पूर्णरूपेण विस्मरण कर देना ही समाधि कहलाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव (सरलता), क्षमा, धैर्य, स्वल्पाहार तथा शुद्धता- ये दस यम बतलाये गये हैं। तप, सन्तोष, आस्तिक भाव, दान, भगवत् ध्यान, वेदान्त श्रवण, ह्री (लज्जा), मति, जप तथा व्रत ये दस नियम कहे गये हैं। अब आसनों के अन्तर्गत स्वस्तिक आदि आसन एवं उनकी विधि का वर्णन करते हैं। दोनों पैरों के तलुओं को दोनों जानुओं (घुटनों) के मध्य में करके बैठना ही स्वस्तिक आसन कहलाता है। पीठ के बायें भाग की ओर दाहिने गुल्फ को तथा दायें भाग की ओर बायें गुल्फ को नियोजित करने से जो गौ (गाय) के मुख की भाँति होता है, वही गोमुख आसन कहलाता है। एक चरण को बायीं जाँघ पर तथा दूसरे (चरण) को दाहिनी जाँघ पर निश्चल भाव से आरोपित करके बैठना ही वीरासन कहलाता है। दाहिनी एड़ी को गुदा भाग के बायीं ओर तथा बायीं एड़ी को गुदा भाग के दाहिनी ओर लगाकर बैठना ही योगासन कहलाता है, ऐसा योगी जन कहते हैं। दोनों जाँघों पर दोनों पैरों के पंजों को प्रतिष्ठित करके बैठना ही पद्मासन कहलाता है। यह आसन समस्त व्याधियों एवं विषों का विनाशक कहा गया है। पद्मासन में अच्छी तरह से आसीन होने के पश्चात् दाहिने हाथ से बायें पैर के अँगूठे को तथा बायें हाथ से दाहिने पैर के अँगूठे को पकड़ना ही बद्धपद्मासन कहलाता है। पद्मासन पर ठीक तरह से स्थित होकर दोनों हाथों को जानुओं एवं जंघाओं के मध्य से निकाल कर भूमि पर लगा कर शरीर को आकाश में अधर पर प्रतिष्ठित रखना कुक्कुट आसन कहलाता है। कुक्कुट आसन लगाने के बाद दोनों भुजाओं से दोनों कन्धों को आबद्ध कर कच्छप के सदृश एक सीध में हो जाना ही उत्तान कूर्मासन कहलाता है। दोनों पैरों के अँगूठों को हाथ से पकड़कर श्रवण रन्ध्रों (कानों) तक धनुष के आकार में कर्ण तक आकृष्ट करना ही धनुरासन कहलाता है। दोनों एड़ियों से सीवन- प्रदेश को विपरीत विधि से दबाकर दोनों घुटनों एवं हाथों को विस्तीर्ण कर स्थिर होना सिंहासन कहलाता है।

क्रमशः ...

विश्व पेपर बैग दिवस

विशाखा सिंह

पेपर बैग डे मनाने का सटीक इतिहास ज्ञात नहीं है। हालाँकि, यह दिन विलियम गुडेल द्वारा निर्मित पेपर बैग मशीन के पेटेंट की याद दिलाता है। उनकी मशीन का पेटेंट 12 जुलाई 1859 को हुआ था और इसलिए हर साल इसी दिन पेपर दिवस भी मनाया जाता है।

क्या आप जानते हैं विश्व में प्रति वर्ष 400 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है? औसतन, प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग सिर्फ 25 मिनट के लिए किया जाता है। साथ ही, एक प्लास्टिक को गलने में कम से कम 100 से 500 साल लगते हैं। इसलिए प्लास्टिक बैग के बजाय पेपर बैग के उपयोग के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 जुलाई के दिन पेपर बैग डे मनाया जाता है।

प्लास्टिक बैग का उपयोग एक वैश्विक चिंता का विषय है जो न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है। इसलिए पेपर बैग डे लोगों को प्लास्टिक बैग के खतरनाक दुष्प्रभावों के बारे में सूचित और शिक्षित करता है। यह दिवस पूरी तरह से भविष्य की पीढ़ी के लिए पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को पेपर बैग चुनने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है।

पेपर बैग का व्यावसायिक निर्माण पहली बार 1844 में इंग्लैंड में किया गया था। हालाँकि, पेपर बैग का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाली मशीन का आविष्कार सबसे पहले 1852 में एक स्कूल शिक्षक फ्रांसिस वोले ने किया था। उन्होंने और उनके भाई ने अपनी मशीन का पेटेंट कराया और यूनियन पेपर बैग कंपनी की स्थापना की। इंग्लैंड में बर्मिंघम और किंग्स नॉर्टन के एक अन्य कागज निर्माता को 1853 में चौकोर तले वाले पेपर बैग बनाने के उपकरण के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ। पेपर बैग बनाने के लिए एक और पेटेंट 1859 में विलियम गुडेल को उनकी पेपर बैग मशीन के लिए दिया गया। मार्गरेट ई. नाइट ने एक मशीन का आविष्कार किया फ्लैट-तले वाले पेपर बैग का उत्पादन करना जो पिछले लिफाफा-शैली डिज़ाइन से अधिक ले जा सकता है। उन्होंने 1870 में ईस्टर्न पेपर बैग कंपनी की भी स्थापना की। 1883 में, चार्ल्स स्टिलवेल ने एक ऐसी मशीन का पेटेंट कराया, जो चौकोर तले और प्लीटेड किनारों वाले पेपर बैग बनाती थी, जिससे उन्हें मोड़ना और स्टोर करना आसान हो जाता था।

प्लास्टिक बैग की तुलना में पेपर बैग का उपयोग करने के कई फायदे हैं। वे पुनर्चक्रण योग्य, पुन: प्रयोज्य और अत्यधिक बायोडिग्रेडेबल हैं जो उन्हें पर्यावरण के लिए कम हानिकारक बनाता है। पेपर बैग आमतौर पर दो से पांच महीने की बहुत ही कम अवधि में खराब हो जाते हैं। औसतन, पेपर बैग के रेशों का यूरोप में 3.6 बार और दुनिया के बाकी हिस्सों में 2.4 बार पुन-उपयोग किया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से, पेपर बैग प्लास्टिक बैग की तुलना में अधिक सुरक्षित होते हैं क्योंकि इससे छोटे बच्चों, जानवरों, समुद्री जीवों को दम घुटने का खतरा कम होता है।पेपर बैग डे हर किसी से प्लास्टिक बैग का उपयोग बंद करने का आह्वान करता है। प्लास्टिक बैग हमारे पर्यावरण को कई नुकसान पहुंचाता है। प्लास्टिक पर्यावरण पर जो दुष्प्रभाव डाल रहा है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और न ही किया जाना चाहिए।

मोदी समुदाय की मानहानि और राहुल गांधी का मुकदमा

आनंद पांडे

23 जुलाई को गुजरात उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की उस पुनर्विचार याचिका को अस्वीकार कर दिया जिसमें उन्होंने मानहानि के मामले में दी गयी सजा पर रोक लगाने की अपील की थी। गुजरात उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई के बाद यह कहा कि %ऐसा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से यह माना जाये कि याचिकाकर्ता के प्रति अधीनस्थ न्यायालय के फैसले पर रोक न लगाने से कोई अन्याय होगा।% फिलहाल यह मुकदमा कानूनी पेचीदगी और प्रक्रिया के हवाले है। अब इस पर फैसला उच्चतम न्यायालय से ही संभावित है। इस मामले को समग्रता में समझने की जिज्ञासा और जरूरत स्वाभाविक है। यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 499 (मानहानि) के प्रावधानों के तहत मानहानि का मुकदमा किन शर्तों के पूरा होने पर बन सकता है। साथ ही राहुल गांधी पर लगे आरोपों पर संहिता के प्रावधानों के तहत विचार भी करते हैं।

13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में राहुल गांधी के भाषण के एक अंश को लेकर उसी वर्ष यह मुकदमा दर्ज हुआ था। उन्होंने कहा था, मेरे मन में एक सवाल है। इन सभी चोरों के नाम मोदी, मोदी, मोदी क्यों हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। थोड़ा और खोजने पर और भी बहुत सारे मोदी निकलेंगे। उसके बाद सूरत पश्चिम से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था। अपनी शिकायत में उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी के इस कथन से मोदी समुदाय की मानहानि हुई

है। अब देखने की जरूरत है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) के तहत क्या यह मुकदमा बनता है? शिकायतकर्ता ने कहा है कि इससे मोदी समाज की मानहानि हुई है। जबकि उक्त धारा में समुदाय, जाति या सम्प्रदाय का जिक्र न होकर व्यक्ति की मानहानि का जिक्र है। धारा के अध्ययन से पता चलता है कि मानहानि किसी व्यक्ति की ही हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति के कथन से किसी समुदाय की मानहानि हो तो उसके लिए दूसरे आरोप लगाये जा सकते हैं। कांग्रेस भी यह कहती रही है कि इस आधार पर मुकदमा बनता ही नहीं है। इसी से जुड़ा तर्क यह भी दिया जा रहा है कि जब उक्त भाषण में पूर्णेश मोदी का नाम नहीं लिया गया तो उनके नाम से शिकायत कैसे दर्ज हो सकती है?

यदि समुदाय की मानहानि का मामला बनता भी हो तो उक्त भाषण से सारे मोदी चोर हैं का आशय निकालना भाषाई दृष्टि से विवेकपूर्ण नहीं है। भाषण के अंश में आये शब्द बहुत सारे मोदी और निकलेंगे से भी सारे मोदी का अर्थ नहीं निकलता है। राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट में दर्ज कराए अपने बयान में यही स्पष्टीकरण दिया था कि उनके बयान का मतलब पूरे मोदी समुदाय से नहीं था। मानहानि मुकदमे से जुड़ा एक तथ्य और है कि कानून के मुताबिक किसी व्यक्ति पर लगाया गया आरोप झूठा हो तभी मानहानि का मुकदमा चलाया जा सकता है। नीरव मोदी, ललित मोदी पर तो हजारों करोड़ रुपये लेकर देश से भाग जाने के तथ्य सम्मत आरोप हैं। इसे कैसे झूठा कहा जा सकता है? नरेंद्र मोदी पर तो उस समय राफेल डील को लेकर चौकीदार चोर है के नारे खुलेआम राहुल गांधी लगा रहे थे। यदि मुकदमा इस सन्दर्भ में चला होता तो चल सकता था पर जिस मामले के जरिए राहुल गांधी पर मुकदमा चलाया गया वह तथ्यात्मक रूप से पूरे मोदी समुदाय की मानहानि कैसे साबित होती है? कानूनन मानहानि का आरोप तभी स्वीकार्य हो सकता है जब वह एक कथन के रूप में रखा जाय, मेरी राय है के रुप में नहीं। राहुल गांधी ने कोई कथन न देकर एक सवाल की शक्ल में बात रखी थी। इस आधार पर भी मुकदमा चलाने की बात पर आम राय नहीं है, और विधिक बहसों में रियायत की जगह बन सकती है। इसके अलावा मानहानि के मामले में आरोपी के खिलाफ मामला चलाने की एक शर्त यह है कि ऐसा करते समय आरोपी की मंशा खराब हो। राहुल गांधी की मोदी समुदाय की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने की कोई मंशा हो सकती हो, और उससे उन्हें कोई लाभ हो सकता हो, यह बात भी अब तक साबित नहीं हुई है। अतीत में मोदी समुदाय को लेकर ऐसा कोई पूर्वाग्रह उन्होंने कहीं प्रकट किया हो, ऐसा देखने में नहीं आया है।

मानहानि के मुकदमें में भारतीय दंड संहिता में यह व्यवस्था भी की गई है कि आरोपी तीन प्रावधानों के तहत अपने को बरी करने की मांग कर सकता है। पहला, सम्बंधित व्यक्ति पर की गई टिप्पणी प्रकाशित और सत्य हो, दूसरा, टिप्पणी जनहित में की गई हो और सत्य हो, तीसरा टिप्पणी करने वाला व्यक्ति जज या सांसद जैसा विशेषाधिकार प्राप्त हो। राहुल गांधी के मामले में देखें तो उन्हें उक्त प्रावधानों के तहत राहत मिल सकती है। तीसरा प्रावधान थोड़ा व्याख्या की मांग करता है जो इस प्रकार हो सकती है = संसदीय नियम है कि एक सांसद को संसद में बोलने पर कोई मुकदमा नहीं दर्ज हो सकता है। उक्त भाषण के समय राहुल गांधी सांसद थे पर भाषण संसद से बाहर था। यही भाषण यदि उन्होंने संसद में दिया होता तो कोई मामला नहीं बनता। अब जबकि संसद की कार्यवाही का लाइव प्रसारण किया जाता है तो एक सांसद के संसद में बोलने या संसद के बाहर बोलने में कोई अंतर करना तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता है। दोनों ही स्थितियों में उसके वक्तव्य लोकमानस तक पहुंचते हैं। ऐसे में संसद में बोलने से बात और उसका असर वही होता है जो संसद के बाहर बोलने से होता है। सुप्रीम कोर्ट में अगर ऐसे तर्क राहुल गांधी के वकील पेश करते हैं और उनके विशेषाधिकार पर बल देते हैं तो उन्हें रियायत की संभावना बन सकती है। पर अब तो निचली अदालत और हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। भारतीय न्यायालय के फैसले ही अंत में निर्णायक होते हैं। उन्हें सबको स्वीकार करना पड़ता है। निश्चय ही राहुल गांधी को भी स्वीकार करना पड़ेगा। परन्तु सूरत के अधीनस्थ न्यायालय के फैसले और उस पर उच्च न्यायालय की मुहर के बाद भी मामले को केवल न्यायायिक रूप में नहीं देखा जा रहा है। यह फैसला विधिवेत्ताओं के साथ साथ राजनीतिक टीकाकारों द्वारा भी देखा जा रहा है।

बापू की दिनचर्या

सायंकालीन प्रार्थना

दक्षिण अफ्रीका में शाम के भोजन के बाद सात या साढ़े सात बजे प्रार्थना होती। बापू के भारत लौटने पर आहार तथा वायु सेवन के पश्चात् प्रार्थना का क्रम चलता। दक्षिण अफ्रीका में नित्य एक सी प्रार्थना नहीं होती। वहाँ के फिनिक्स आश्रम में सिर्फ शाम को प्रार्थना होती साबरमती में सन् 1927 में सायंकालीन प्रार्थना का समय छह साढ़े छह बजे और सेवाग्राम में सामान्यत: साढ़े सात बजे था। लंदन में गोलमेज परिषद् के समय बापू शाम सात बजे प्रार्थना करते। वहाँ से भारत लौटते समय बापू इटली में रुके थे-रोमा रोलाँ से मिलने वे उस समय भी शाम को ठीक सात बजे प्रार्थना करते। वहाँ वे जमीन पर रोशनी की शेड के नीचे चटाई बिछाकर बैठ जाते और उनके इर्द-गिर्द उनके अनुयायी प्रार्थना में मीरा बहन का गंभीर स्वर विशेष प्रभाव डालता। नोवाखाली यात्रा के समय शाम की प्रार्थना पाँच बजे होती । वे प्रार्थना के बाद वायु सेवन के लिए निकलते। दिल्ली में अंतिम दिनों में शाम की प्रार्थना में वे ठीक पाँच बजे पहुँच जाते। यात्रा या मुसाफिरी में निश्चित समय पर प्रार्थना करने में पहले प्राय: बहुत कठिनाई और गड़बड़ी होती। सन् 1926 का आंध्र के चिकाकोल नामक स्थान का प्रसंग है। बापू प्रवास में थे। वहाँ रात्रि में कत्तिनों का दंगल होनेवाला था, जिसे देखने के लिए वे रुक गए। दिन भर की थकावट थी। दंगल से जब वे अपने स्थान पर पहुँचे तब उन्हें नींद आ गई। रात्रि में दो- ढाई बजे जब उनकी नींद टूटी तब उन्हें याद आया कि आज सायंकालीन प्रार्थना नहीं हुई। उन्हें ऐसा आघात पहुँचा कि उनका शरीर काँप उठा। पसीने से वे तर-बतर हो गए। उठ बैठे और पश्चाताप करने लगे। जिनके अनुग्रह से प्राणी जीवित है, उसकी जीवन-साधना चलती है, उन भगवान का ही विस्मरण हो जाने से उन्होंने इसे अपनी बहुत बड़ी भूल बताते हुए प्रभु से क्षमा-याचना की। इसके बाद बापू की नींद ही भाग गई। वे रात भर बैठे रहे। प्रात: कालीन प्रार्थना में उन्होंने कहा कि प्रवास या यात्राकाल में भी हमें अपनी सायंकालीन प्रार्थना निश्चित समय पर करनी चाहिए।

क्रमशः ...

संक्षिप्त समाचार

योग को दैनिक जीवन में शामिल कर स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं : लखमा

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की प्रेरणा से छत्तीसगढ़ में लगातार स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है। इस दिशा में छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा लोगों को योग से जोड़ते हुए स्वस्थ रखने का प्रयास सराहनीय है। सभी लोग योग को दैनिक जीवन में शामिल कर स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा ने यह बात छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा रायपुर के फुण्डहर स्थित %योग भवन% में बस्तर संभाग के लिए आयोजित सात दिवसीय आवासीय योग प्रशिक्षण शिविर में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर योग आयोग के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश शर्मा भी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि लोगों तक योग के फायदे पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा संभाग स्तरीय योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में रायपुर, बिलासपुर संभाग के बाद का बस्तर संभाग के प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 13 जुलाई तक चलेगा। इसमें बस्तर संभाग के लगभग 150 प्रतिभागी प्रशिक्षण ले रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के 10000 संविदा कर्मचारियों ने निकाली रैली, जेल भरने की चेतावनी

रायपुर। सोमवार को रायपुर में प्रदेश भर से आये संविदा कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। नवा रायपुर स्थित तूता धरना स्थल पर कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए कर्मचारी संघ ने अपनी एक सूत्रीय मांग नियमितीकरण का मुद्दा उठाते हुए आने वाले दिनों में जेल भरो आंदोलन करने की चेतावनी दी। नया रायपुर स्थित धरना स्थिल में संविदा कर्मचारियों ने एक बड़ी सभा लेने के बाद रैली निकाली। कर्मचारी मंत्रालय की ओर बढ़े, तो बीच रास्ते में ही पुलिस ने इन्हें रोक दिया। कर्मचारियों ने प्रशासनिक अफसरों को बुलाने के लिए कहा, लेकिन मौके पर कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। जिससे गुस्साए कर्मचारियों ने ज्ञापन फाड़ दिया और छत्तीसगढ़ में जेल भरो आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस बीच कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। संविदा कर्मचारियों की रैली को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। संविदाकर्मी महासंघ प्रदेश अध्यक्ष कौशलेश तिवारी ने कहा कि सरकार द्वारा पौने पांच साल बीत जाने के बाद भी नियमितिकरण पर कोई निर्णय नहीं लेने से संविदा कर्मियों में नाराजगी है। सरकार ने ही हमें आन्दोलन करने पर मजबूर किया है। सरकार से हमारी मांग है कि अनुपूरक बजट पेश कर प्रदेश के सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित करें। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदाकर्मी महासंघ ने सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं करने पर आने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता बदलने की चेतावनी दी है।

17 और 20 जुलाई को नौ ट्रेन रद, आठ ट्रेन देरी से रवाना होंगे

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल के अंतर्गत दुर्ग-भिलाई नगर के बीच रोड ओवर ब्रिज पर गार्डर लांचिंग का काम 17 और 19 जुलाई को लेवल क्रासिंग नंबर 442 पर किया जाएगा। इस बीच 17 जुलाई की रात एक बजे से सुबह छह बजे तक और 19 जुलाई को रात 11 बजे से 20 जुलाई की दोपहर 3.40 बजे तक रेलवे ने ब्लाक लिया है, ताकि रोड ओवर ब्रिज का काम बिना किसी परेशानी के पूरा किया जा सके। रेलवे प्रशासन ने गार्डर लांचिंग के चलते 17 और 20 जुलाई को नौ ट्रेनों को रद करने के साथ ही आठ ट्रेनों को देरी से रवाना करने का फैसला लिया है। ट्रेनें रद होने से यात्रियों को हमेशा की तरह परेशान होना पड़ेगा। 17 और 20 जुलाई को रायपुर से चलने वाली 08701 रायपुर-दुर्ग मेमू पैसेंजर स्पेशल,दुर्ग से चलने वाली 08702 दुर्ग-रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल,डोंगरगढ़ से चलने वाली 08730 डोंगरगढ़- रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल,डोंगरगढ़ से चलने वाली 08710 डोंगरगढ़-रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल रद रहेगा। वहीं 16 और 19 जुलाई को गेवरा रोड से चलने वाली 18239 गेवरा रोड-इतवारी एक्सप्रेस, 16 व 19 जुलाई को टाटानगर से चलने वाली 18109 टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस,16 व 19 जुलाई को इतवारी से चलने वाली 18240 इतवारी-बिलासपुर एक्सप्रेस,17 व 20 जुलाई को इतवारी से चलने वाली 18110 इतवारी-टाटानगर एक्सप्रेस,16 व 19 जुलाई को रायपुर से चलने वाली 08729 रायपुर-डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर स्पेशल रद रहेगी।

चर्च ऑफ नार्थ इंडिया के मॉडरेटर द मोस्ट रेवरेंड नायक आएंगे आज

रायपुर। चर्च ऑफ नार्थ इंडिया के मॉडरेटर द मोस्ट रेवरेंड बिजय कुमार नायक 12 जुलाई को एक दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे है। उनके साथ डिप्टी मॉडरेटर द राइट रेवरेंड पॉल बी. पी. दुपारे, सिनड के कोषाध्यक्ष सुब्रता गोराई भी पहुंचेंगे। इसके अलावा यूसीएनआईटी, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, पंजाब, प. बंगाल व उत्तरप्रदेश से भी बिशप, पादरियों व सीएनआई के पदाधिकारियों भी आएंगे। यह जानकारी प्रवक्ता जॉन राजेश पॉल ने दी।छत्तीसगढ़ डायसिस के बिशप द राइट रेवरेंड अजय उमेश जेम्स की अगुवाई में सिनड के पदाधिकारियों के आगमन व कार्यक्रमों की तैयारी चल रही है। बिशप जेम्स ने बताया कि यह पहला अवसर है जब छत्तीसगढ़ में सिनड के एक साथ इतने डिग्निटरीज आ रहे हैं। वे कई आत्मिक व विकास कार्यों के लिए मार्गदर्शन देंगे।

पिछले साढ़े चार वर्षों में 838 स्टार्ट-अप इकाईयां हुई पंजीकृत

स्टार्ट-अप रैकिंग 2021 में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के विकास के लिए छत्तीसगढ़ एस्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मानित

■ **नवीन औद्योगिक नीति में पहली बार इनक्यूबेटर्स की स्थापना एवं संचालन के लिए अनुदान का प्रावधान**

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू नवीन औद्योगिक नीति (2019-24) में स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गई नीतियों का परिणाम है की पिछले साढ़े चार वर्षों में 838 स्टार्ट-अप इकाईयां पंजीकृत हुई हैं। नवीन औद्योगिक नीति में पहली बार इनक्यूबेटर्स की स्थापना एवं संचालन के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा लागू नीतियों एवं इनके उचित क्रियान्यवन से राज्य की स्टार्ट-अप इकाईयां देश में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुई है। जून 2022 में बेंगलुरू में आयोजित ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन द्वारा आयोजित इंडिया फर्स्ट टेक स्टार्ट-अप कॉनक्लेव में राज्य के स्टार्ट-अप को चार श्रेणियों में बेस्ट स्टार्ट-अप का आवार्ड मिला है।

इसी तरह जुलाई 2022 में भारत सरकार द्वारा घोषित स्टेट्स स्टार्ट-अप रैकिंग 2021 में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के विकास के लिए राज्य को एस्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मानित किया गया। राज्य में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग भारत सरकार से मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप इकाईयों की संख्या वर्तमान में 1012 हैं, जिसमें से 838 स्टार्ट-अप इकाईयां पिछले साढ़े चार वर्षों में पंजीकृत हुई है। स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए इनक्यूबेटर्स की स्थापना हेतु किए गए व्यय का 40 प्रतिशत, अधिकतम 50 लाख रूपये और संचालन करने पर 3 वर्षों के लिए अधिकतम 3 लाख प्रतिवर्ष का संचालन अनुदान इत्यादि दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रोत्साहन के लिए ब्याज अनुदान में अधिकतम 70 प्रतिशत, 55 लाख रूपये की सीमा तक, अधिकतम 11 वर्षों के लिए दिया जा रहा है। स्थायी पूंजी निवेश में अनुदान अधिकतम 55 प्रतिशत है, इसकी अधिकतम सीमा 24 लाख रूपए है। नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से अधिकतम 15 वर्षों तक स्थायी पूंजी निवेश का 100 प्रतिशत तक छूट दी गई है। विद्युत शुल्क से छूट वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से अधिकतम 10 वर्षों तक पूर्ण छूट का लाभ दिया गया है। भूमि के क्रय या लीज पर स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट दिया गया है।

किराया अनुदान में भुगतान किये गये मासिक किराये का 40 प्रतिशत, प्रतिमाह अधिकतम राशि 8000 रूपये की प्रतिपूर्ति दी जा रही है। परियोजना प्रतिवेदन अनुदान के तहत मान्य स्थायी पूंजी निवेश का एक प्रतिशत, अधिकतम राशि 2.50 लाख रूपये तक की सीमा निर्धारित की गई है। गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान के अंतर्गत 50 प्रतिशत अधिकतम राशि 5 लाख रूपए तक निर्धारित है। तकनीकी पेटेंट अनुदान के तहत किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि 10 लाख रूपये है। प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान के अंतर्गत किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि 10 लाख रूपये की सीमा निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय योजना में भाग लेने हेतु अनुदान- राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमीनार एवं वर्कशॉप में भाग लेने पर 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति अधिकतम एक लाख प्रतिवर्ष की सीमा तक किया जा सकता है। उद्योग विभाग, सीएसआईडीसी के औद्योगिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक पार्कों में भूमि आबंटन पर भू-प्रब्याजी में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।

अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी पूरे देश के लिए शुभ: केदार गुप्ता

■ **ये संकेत छत्तीसगढ़ को भी मिल चुका है**

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी का सिलसिला गर्म है। जमकर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी पूरे देश के लिए शुभ हैं। अब ये शुभ संकेत दोनों छत्तीसगढ़ को मिल चुका है। अमित शाह और पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ आना शुभ होगा। समय बदलता है, थोड़ा इंतजार कीजिए और याद रखिए।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास को भूपेश बघेल की सरकार ने रोक रखा है। गरीबों को मकान क्यों नहीं दे रही?। कांग्रेस के प्रेस बीफ के बयान पर केदार गुप्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि अभी कल पहली प्रेस बीफ भी हुई है, उससे कांग्रेस इतना घबरा गई। तंज कसते हुए कहा कि लबरा पार्टी के लोग हैं झूठ बोलने वाले लोग हैं। कसम खाई थी कि घोषणापत्र के काम पूरा करेंगे। टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस के घोषणा पत्र समिति में रहने से इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि घोषणा मेरे से करवाते हैं और पूरा नहीं करते हैं।

टीएस सिंहदेव राजा है। टीएससिंह देव ने पार्टी में बड़ा दबाव बनाकर डिप्टी सीएम का पद पाया है। कांग्रेस के चिंदी चोर वाले बयान पर केदार गुप्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस जब से सत्ता में आई है तब से उसके बोल बिगड़ गए हैं। एहसान फरामोश और झूठ बोलने वाली कांग्रेस है। किसी भी राजनीतिक पार्टी का घोषणा पत्र गंगाजल जैसा पवित्र होता है। 94 लाख धान का चावल पीएम मोदी ने लिया है। धान के लिए 22000 करोड़ दिया है। कांग्रेस को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी भाषा सुधारे। अपना दिमाग छत्तीसगढ़ के विकास की ओर लगाए। नहीं तो ये जो विध्वंस कर रहे हैं यह होता ही रहेगा।

भेंट-मुलाकात के बाद अब युवाओं से सीधे संवाद करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सभी वर्ग के नागरिकों से विधानसभावार भेंट-मुलाकात कार्यक्रम पूरे होने के बाद अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के युवाओं से संभागवार सीधे संवाद करेंगे। इस खास आयोजन के दौरान वे युवाओं से उनके मुद्दों, उपलब्धियों और आकांक्षाओं पर बात करेंगे। वे युवाओं के प्रश्नों के जवाब भी देंगे।

छत्तीसगढ़ में राजीव युवा मितान क्लब के गठन से युवा-ऊर्जा को सकारात्मक दिशा मिली है। इन क्लबों के माध्यम से युवा अपने-अपने क्षेत्रों में रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। उनमें काफी उत्साह है। संभागस्तरीय आयोजन के दौरान युवा अपने अनुभव साझा करेंगे, ताकि उनके अनुभव का लाभ अन्य लोग भी उठा सकें। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे और युवा भी अपनी बात साझा करेंगे। वे मुख्यमंत्री से प्रश्न भी पूछ सकेंगे। कार्यक्रम में सभी वर्ग के युवाओं का प्रतिनिधित्व होगा।

साढ़े चार सालों में युवा हित में कई निर्णय लिए

मुख्यमंत्री ने साढ़े चार सालों में युवा हित में अनेक निर्णय लिये हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस माफी के साथ ही राज्य में रोजगार मिशन का संचालन किया जा रहा है। साढ़े चार सालों में बड़े पैमाने पर शासकीय भर्तियां की गई हैं। हाल ही में रोक होने के बाद और लगभग 20 हजार शासकीय पदों भर्तियां की जा रही हैं। रोजगार मेलों का आयोजन कर बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक लाख 17 हजार से अधिक युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की राशि हर महीने प्रदान की जा रही है। अब तक 80 करोड़ रुपए की राशि युवाओं के खाते में अंतरित की जा चुकी है। इसके अलावा राज्य की खेल अधोसंरचना को भी मजबूत किया गया है।

केंद्र ने महरा और महार समुदाय को एससी में शामिल करने की मंजूरी दी

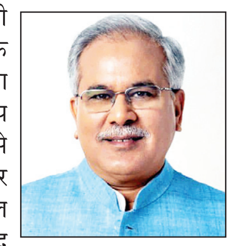

रायपुर/दिल्ली। छत्तीसगढ़ में चुनावों से पहले, केंद्र सरकार राज्य के दो उप समुदायों को एससी सूची में लाने की तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ के महरा और महार उप समूहों को एक कानून के माध्यम से एससी सूची में शामिल किया जाएगा। जिसे संसद के मानसून सत्र में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से पेश किया जाएगा। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा भूपेश बघेल सरकार की सिफारिश पर अपनी सहमति देने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मई को अपनी बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

अनुसूचित जाति में शामिल होगी महारा और महरा-महारा, महरा जाति को महार, मेहरा, मेहर के पर्यायवाची के रूप में शामिल किया जाएगा। वे छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति की सूची में पहले से मौजूद नामों के ध्वन्यात्मक रूप मात्र हैं। इस कदम से एक लंबे समय से चली आ रही शिकायत का समाधान हो जाएगा। जिसके तहत छत्तीसगढ़ में महार आबादी का लगभग आधा हिस्सा दलित वर्ग से वंचित था। इससे उन्हें नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के साथ-साथ अनुसूचित जाति के लिए उपलब्ध अन्य सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा था। इस कदम से लंबे समय से चली आ रही विसंगति दूर हो जाएगी। जिसके तहत आधे महार समुदाय को ध्वन्यात्मक भिन्नता के कारण दलित के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। सूत्रों के अनुसार 2002 में केंद्र ने 1989 में अविभाजित मध्य प्रदेश की तरफ से भेजे गए एक प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की, और एससी की सूची में एमपी की महारा जाति को शामिल करने के लिए एक गजट अधिसूचना जारी की। चूंकि छत्तीसगढ़ को 2000 में मध्य प्रदेश से अलग कर बनाया गया था, इसलिए केंद्र ने नए राज्य के रायपुर और बस्तर क्षेत्रों में मौजूद समुदाय को छोड़ दिया। महार, माहरा, महरा का चुनावी महत्व है क्योंकि कहा जाता है कि वे बस्तर क्षेत्र के लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और चुनावों में जीत हार का निर्णय कर सकते हैं। जैसे ही विधेयक संसद में पारित हो जाएगा, अनुसूचित जाति के बीच महार समुदाय की आबादी लगभग दोगुनी हो जाएगी।छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 32.74 लाख है, जो राज्य की जनसंख्या का 12.82 प्रतिशत है। जबकि महार, मेहरा, मेहर की आबादी 2.45 लाख है, महारा, महरा, जिन्हें अब एससी सूची में शामिल किया जाना है, उनकी संख्या लगभग 2 लाख है।

मुख्यमंत्री से जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री बघेल से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल द्वारा एसोसिएशन के संबंध में चर्चा की गई। इस अवसर पर एसोसिएशन के पदाधिकारी डॉ. प्रेम चौधरी, डॉ. गौरव परिहार, डॉ. प्रीतम प्रजापति, डॉ. हिमांशु सिन्हा तथा डॉ. गगन मोहन आदि उपस्थित थे।

भाजपा झूठ के आधार पर राजनीति कर रही है : सुशील आनंद शुक्ला

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पत्रकारो को संबोधित करते हुये कहा कि मुद्दाविहीन भाजपा छत्तीसगढ़ में झूठ के आधार पर राजनीति कर रही है। पहले ईडी को भेजकर गलत कार्यवाही करवाई जाती है, फिर ईडी के द्वारा तैयार की गयी पटकथा के आधार पर कांग्रेस सरकार पर घोटाले के झूठे आरोप लगाये जाते है। ईडी कार्यवाही करती है भाजपा नेता बयान देकर उसके राजनीति करते है इससे साबित होता है कि ईडी की कार्यवाही भाजपा की राजनैतिक साजिश का नतीजा है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर साढ़े चार साल में एक भी रू. का भ्रष्टाचार का प्रमाणिक आरोप नहीं लगा पाने वाली भाजपा ने सरकार को बदनाम करने ईडी को आगे कर साजिश रचा और घोटाले के झूठे आरोप प्रचारित किये जा रहे है। प्रधानमंत्री ने अपने पद की मर्यादा को तार-तार कर शराब बंदी से शराब घोटाले का जोड़ कर झूठ बोला।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा नेता ईडी की पटकथा के आधार पर आरोप लगा रहे की छत्तीसगढ़ में बिना एक्साइज ड्यूटी पटाये शराब बिक्री करने से 2168 करोड़ का घोटाला हुआ है। यदि ईडी के आरोप सही है तो ईडी ने शराब निर्माण के विक्रय के डिस्टलरो के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं किया? ईडी की कार्यवाही कही सुनी बातो के आधार पर बिना तथ्य के है। राज्य मे 2012 मे रमन सरकार ने देशी शराब के उत्पादन का अधिकार मात्र राज्य के ही मात्र 3 डिस्टलरों को मिल गया था अन्य किसी डिस्टलर को उत्पादन निविदा मे भाग लेने का अधिकार समाप्त हो गया था। रमन सरकार ने ही 2017 मे शराब विक्रय का एकाधिकार सरकारी कम्पनी को सौपा। शराब करोबार के लिए मेन पावर प्लेस मेन्ट एजेंसियो से लेना शुरू किया तथा देशी शराब कि आपूर्ति पूर्व पंजीकृत 3 ठेकेदारों से होती रही।

विद्यार्थियों को प्राथमिकता के तौर व्यसन मुक्ति के लिए किया जाएगा जागरूक

स्वयं सेवी संस्थाओं, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाओं से लिया जाएगा सहयोग

■ **नशा मुक्ति जन-जागरूकता अभियान के तहत कार्ययोजना प्रारूप का संशोधन एवं सुझाव कर बैठक संपन्न**

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में नशा मुक्ति के लिए व्यापक स्तर पर जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा जोर-शोर से इसके लिए तैयारी की जा रही है। नशा मुक्ति अभियान के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्ययोजना (प्रारूप) तैयार कर ली गई है। आज कार्ययोजना (प्रारूप) में संशोधन एवं सुझाव के लिए बैठक आयोजित की गई।

नशा मुक्ति अभियान के लिए तैयार प्रारूप में संशोधन एवं सुझाव हेतु आयोजित बैठक में चर्चा के दौरान विभागीय समन्वय और शासकीय, गैर शासकीय, स्वयं सेवी संस्थाओं तथा धार्मिक व समाजिक संस्थाओं का सहयोग लिए जाने पर विशेष बल दिया गया। बैठक में स्कूलों, कॉलेजों, पारा-मोहल्लों में आदिवासी पारम्परिक संस्कृति को बिना प्रभावित किए हुए नशा मुक्ति अभियान चलाए जाने पर जोर दिया गया। समाज को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने, युवा पीढ़ी को बर्बादी से बचाने तथा उनकी संपूर्ण ऊर्जा का राष्ट्र निर्माण में उपयोग करने के लिए आवश्यक है कि नशा मुक्ति हेतु बड़ा जन-जागरण अभियान आरंभ किया जाये। उच्चतर माध्यमिक शालाओं, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के छात्रों में जागरूकता हेतु लेखन, कविता, भाषण, प्रतियोगिता सहित सेमीनार आदि का आयोजन किया जाए। बैठक में समाज कल्याण विभाग के अपर संचालक श्री पंकज वर्मा सहित संबंधित विभागीय अधिकारी और स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि विशेष रूप उपस्थित थे।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में नशे के दुष्प्रभावों से समाज को बचाने के लिए व्यापक जन-जागरण अभियान आरंभ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नशा मुक्ति जन-जागरण अभियान की विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के लिए देश में नशा मुक्ति हेतु कार्य कर रहे ख्यातिनाम व्यक्तियों एवं संस्थाओं से आवश्यक रूप से परामर्श किया जाए। समाज कल्याण विभाग द्वारा नशा मुक्ति जन-जागरण अभियान के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर ली गई है। प्रारूप में संशोधन एवं सुझाव के लिए बैठक में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों ने कहा कि नशा एक ऐसी गंभीर सामाजिक बुराई है, जिससे मनुष्य का अनमोल जीवन गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है तथा वह अकाल मृत्यु का भी शिकार बन जाता है। नशे के लिए लोगों द्वारा गांजा, भांग, जर्दा गुड़ाखू, तंबाकू, शराब, गुटका, धूम्रपान, चरस, अफीम, स्मैक, कोकीन और ब्राउन शुगर तथा सुंघकर की जाने वाली नशा जैसे मादक पदार्थों का सेवन किया जाता है। इसे रोकने के लिए शासकीय प्रयासों के साथ ही जनभागीदारी जरूरी है। जब तक हम इस अभियान को जनमानस से नहीं जोड़ेंगे तथा जन-जन तक नहीं पहुंचायेंगे, तब तक यह अभियान सफल नहीं हो पाएगा। युवा पीढ़ी में नशे की प्रवृत्ति तेजी से बढना अत्यधिक चिंताजनक विषय है।

ओलंपिक खेलों के दौरान पिछले वर्ष की तरह लापरवाही न हो : साव

■ खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और जान की चिंता करे कांग्रेस सरकार

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आगामी 17 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के मद्देनजर प्रदेश सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए खिलाड़ियों की सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने की मांग की है। श्री साव ने कहा कि लगभग ढाई माह तक 6 चरणों में होने वाले ओलंपिक में चूंकि बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक प्रतिभागी होंगे, अत: प्रदेश सरकार इस आयोजन की तमाम व्यवस्थाएँ चाक-चौबंद रखे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि पिछली बार छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन में अनेक प्रतिभागियों की मृत्यु हो गई थी। प्रदेश सरकार को इस बार विशेष ध्यान रखना होगा, इस बार एक भी जान सरकारी अव्यवस्था और लापरवाही के कारण न जाए, प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा। श्री साव ने कहा कि पिछली बार के आयोजन में जितनी मौतें हुई थी, उन मृतकों के परिजनों को अभी तक उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में मुआवजा बाँटकर प्रदेश का खजाना लुटाने वाली प्रदेश की कांग्रेस सरकार पिछले ओलंपिक आयोजन के मृतक परिवारों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दे और इस बार के आयोजन से पहले सभी प्रतिभागियों का बीमा कराया जाए। श्री साव ने कहा कि सभी प्रतिभागी प्रदेश की प्रतिभा संपन्न धरोहर हैं। उनकी सुरक्षा और सुविधाओं में कोताही बरतना प्रदेश सरकार की नाकामी का एक और काला अध्याय होगा।

मुख्यमंत्री की युवाओं संग मुलाकात पर बोली भाजपा

फिर सुनने मिलेगा ऐ लड़की नेतागिरी मत कर और कभी तेरे बाप ने माइक पकड़ा है

रायपुर। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रस्तावित संभागवार युवाओं से संवाद कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि कथित भेंट मुलाकात वास्तविक रूप से डांट डपट कार्यक्रम की तरह एक बार फिर छत्तीसगढ़ के युवाओं को सुनने मिलेगा कि ऐ लड़की नेतागिरी मत कर और यह भी सुनने मिलेगा कि कभी तेरे बाप ने माइक पकड़ा है। मुख्यमंत्री घूम -घूम कर पूरे छत्तीसगढ़ के युवा बेटे -बेटियों का भरपूर अपमान कर चुके हैं। अब और कौन सी कसर बाकी रह गई जो अब फिर से युवाओं को डांटने डपटने का दौर शुरू कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रायोजित कार्यक्रम का वह वायरल वीडियो देखा है कि किस तरह प्रशिक्षण दिया जाता है कि जनता के सामने मुख्यमंत्री क्या- क्या पूछेंगे और किस तरह से कौन से जवाब देने हैं मुख्यमंत्री में हिम्मत है तो प्रायोजित युवाओं से नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के उन युवाओं से मिलें।

कांग्रेस सरकार को शराब की अवैध कमाई की लत लगी: बृजमोहन अग्रवाल

रायपुर। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता व छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मंत्री मोहम्मद अकबर की प्रेसवार्ता पर जवाबी हमला बोला हैं। उन्होंने मोहम्मद अकबर को ये तक कह दिया कि आने वाले समय में मोहम्मद अकबर की भी वहीं गति होगी जो टीएस सिंहदेव की हुई हैं।

सोमवार को मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में अकबर ने भाजपा पर झूठ पर आधारित राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गंगाजल हाथ में लेकर सिर्फ किसानों के कर्जा माफी की बात की थी। जिसे पूरा कर दिखाया। भाजपा का ये आरोप झूठा है कि कांग्रेस ने गंगाजल हाथ में लेकर शराबबंदी का वादा किया था। अकबर ने आगे कहा कि 15 साल तक तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रदेश में शराबबंदी का ऐलान किया था जिसे वे पूरा नहीं कर सके। प्रेसवार्ता में मंत्री अकबर ने प्रूफ के तौर पर वीडियो भी दिखाया।

मंत्री अकबर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बृजमोहन भड़क गए और कहने लगे कि कांग्रेस सरकार को शराब की अवैध कमाई की लत लग गई है। यह सरकार लतखोर हो गई है। रोज नई-नई बातें करती है। कम से कम मो। अकबर को तो गंगाजल के बारे में बात नहीं करना चाहिए। नई नई बात करके, नए नए मुद्दे उछाल रहे हैं। कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक कर देखें।

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा मोहम्मद अकबर आने वाले समय में कांग्रेस में आपकी वहीं गति होने वाली है जो गति टीएस सिंहदेव की हुई हैं। जो कांग्रेस के जनघोषणा पत्र के प्रमुख थे, जो अब सिर छिपाकर घूम रहे हैं। आने वाले समय में आपकी भी वहीं स्थिति होगी।

अग्रवाल ने आगे कहा कि रोज नये बहाने कर कांग्रेस अपना पाप ढक नहीं सकती। कभी कहते हैं कि बेरोज़गारी भत्ता की बात नहीं की थी, कभी कह रहे हैं शराबबंदी का वादा नहीं किया था। प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि किस तरह इन्होंने गंगाजल हाथ में लेकर सारे वादे किया थे। लेकिन अब इनकी चलाचली की बेला है।

शिक्षकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, 18 को जंगी प्रदर्शन

रायपुर। 31 जुलाई से शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल परजा रहे हैं। शिक्षकों की हड़ताल का असर स्कूलों और बच्चों की पढ़ाई में भी देखने को मिलेगा। शिक्षकों की हड़ताल से पढ़ाई बाधित होगी। आज हड़ताल के संबंध में छत्तीसगढ़ शिक्षक मोर्चा ने प्रेसवार्ता कर इसकी जानकारी दी। नीचे पढ़ें जारी प्रेसनोट प्रदेश में शिक्षक एलबी संवर्ग जिनकी संख्या लगभग 1 लाख 80 हजार से ज्यादा हैं जिनमे छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन प्रांताध्यक्ष संजय शर्मा, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन प्रांताध्यक्ष मनीष मिश्रा, शालेय शिक्षक संघ प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे, नवीन शिक्षक संघ प्रांताध्यक्ष विकास राजपूत, छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ प्रांताध्यक्ष केदार जैन की 5 जुलाई को राजधानी रायपुर में एकता बैठक की गयी। एलबी संवर्ग के शिक्षकों के भावना और हितो को सर्वोपरि मानते हुए तथा सरकार द्वारा शिक्षको के मांगो पर ध्यान नहीं देने के कारण शासन के विरोध में एकजुट होकर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में सभी संघों द्वारा सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया है। मोर्चा के बैनर तले होने वाले आंदोलन की रणनीति के संबंध में शिक्षक संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने रायपुर प्रेस क्लब में प्रेस कांफ्रेंस में संयुक्त प्रेसवार्ता करते हुए कहा है कि सभी घटक संघ एकजुट हो जाये तथा अपनी पूर्व सेवा की गणना, प्रथम नियुक्ति तिथि से लेने हेतु समन्वय बनाये, प्रेस कांफ्रेंस के बाद मंत्रालय जाकर मुख्यसचिव, प्रमुख सचिव शिक्षा, सचिव वित्त व सामान्य प्रसाशन तथा डीपीआई को हड़ताल की सूचना देते हुए एलबी संवर्ग शिक्षको की एक सूत्रीय मांग पूर्व सेवा की गणना करङ्कसहीं वेतन निर्धारण करते हुए सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर कर/क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान कर, पुरानी पेंशन प्रदान करे एवं कुल 20 वर्ष की पूर्ण सेवा पर पुरानी पेंशन दिया जावे। का ज्ञापन दिया गया।

बुरा कार्य करने से राष्ट्र का गौरव नष्ट हो जाता है: राज्यपाल

रायपुर। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ओडिशा राज्य के प्रवास के दौरान खोरधा जिले में जनता हाईस्कूल कुहुदी के 68वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बुरा कार्य करने से राष्ट्र का गौरव नष्ट हो जाता है।

जनता हाईस्कूल के पूर्व छात्र रहे राज्यपाल हरिचंदन ने मुख्य अतिथि की आसंदी से अपने उद्बोधन में कहा कि आगे बढें और देश के लिए गरिमा के साथ कार्य करें। अपने जीवन को दया और घृणा का पात्र न बनाये बल्कि देश, मातृ भूमि, और मानवता की सेवा में समर्पित करें। उन्होंने कहा कि मातृ भाषा और मानवजाति पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। शोषण किसी भी समुदाय की परंपरा नहीं है। शोषण करके कोई भी राष्ट्र महान नहीं बना। देश के गरीबों के कल्याण तभी होगा जब शोषण का परित्याग होगा।

इस अवसर पर भुवनेश्वर की सांसद सुश्री अपराजिता षडंगी समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थी। कार्यक्रम में स्कूल के पूर्व प्राचार्य विधुभूषण पटनायक, सामाजिक कार्यकर्ता श्री बलवंत राय, अभिभावक एवं शिक्षकगण, स्कूल के वर्तमान एवं पूर्व छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

भूपेश बघेल को विधायिका पर भरोसा नहीं: चंदेल

■ प्रश्न तो पूछे जाएंगे जवाब तो देना पड़ेगा

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मानसून सत्र की कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें विधायिका पर भरोसा नहीं है। 18 जुलाई से 21 जुलाई तक छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आहूत किया गया है। दुर्भाग्य यह है कि इस विधानसभा के पूरे कार्यकाल में, जब से भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने हैं, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, कभी भी विधानसभा का कोई भी सत्र अपनी अवधि पूरा नहीं कर पाया। सत्र की अवधि कम की जाती रही है। इस पर भी जो निश्चित अवधि रही, उसके पहले ही सत्र समाप्त हो गया। यह इस बात का द्योतक है कि भूपेश सरकार विधायिका पर विश्वास नहीं करती। विधायिका का अपमान करती है। वह सदन में चर्चा से भागना चाहती है। सवालों से बचना चाहती है। लेकिन हम भूपेश जी से कहना चाहते हैं कि विधानसभा लोकतंत्र का पावन मंदिर है। सवाल तो पूछे जाएंगे। जवाब तो देना होगा। चाहे सत्र की अवधि में कितनी भी कटौती कर लें।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री को खुद पर भरोसा नहीं है, अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है, इसलिए विधानसभा में चर्चा से भाग रहे हैं। भूपेश बघेल को विधायिका पर विश्वास नहीं है, इसलिए उनके मंत्री और विधायक सदन की कार्यवाही सलीके से चलने नहीं देते। लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, इसलिए विपक्ष को बोलने नहीं देते। जनता के सवालों का जवाब सरकार नहीं देती। उनकी सरकार में कार्यपालिका की क्या स्थिति है, सारा छत्तीसगढ़ जानता है। इनके अफसर भ्रष्टाचार के मामलों में जेल जा रहे हैं और जमानत नहीं मिल रही। न्याय पालिका का सम्मान कांग्रेस के चरित्र में कभी नहीं रहा। भूपेश बघेल संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ धरने पर बैठ जाते हैं।

लाईवलीहुड कॉलेज में पांच शॉर्ट टर्म कोर्स में प्रवेश

■ 8वीं-10वीं पास बेरोजगारों को मिलेगी ट्रेनिंग

रायपुर। रायपुर के जोरा स्थित लाइवलीड कॉलेज में जिले के शिक्षित बेरोजगार पांच शॉर्ट टर्म कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। युवा इन शॉर्ट टर्म कोर्स के द्वारा इलेक्ट्रिशियन, सोलर पम्प टेक्निशियन, डाटा एण्ट्री ऑपरेटर, सेल्स एसोसिएट, टेलरिंग का प्रशिक्षण ले सकते हैं। पूरा प्रशिक्षण नि:शुल्क होगा। इसके साथ ही कम्प्यूटर स्किल, कम्यूनिकेशन स्किल, व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

इन शॉर्ट टर्म कोर्सेस की अवधि 3 से 4 माह की होगी। सफलता पूर्वक ट्रेनिंग लेने के बाद प्रशिक्षणार्थी युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। इन कोर्सेस में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता 8-10 वीं पास होना है। 18 से 45 वर्ष आयु के हितग्राही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेस में प्रवेश के लिए अधिक जानकारी के लिए लाईवलीहुड कॉलेज, जोरा रायपुर के कार्यालय और दूरभाष नंबर 0771-2443066 से संपर्क किया जा सकता हैं।

मौसम विभाग ने चार जिलों के लिए जारी किया यलो अलर्ट

रायपुर। मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के लिए प्रदेश के राजनांदगांव, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर जिलों में एक-दो स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के सभी जिलों में न्यूनतम तापमान का आंकड़ा अब 27 डिग्री के नीचे आ गया है।मौसम विभाग ने आज दोपहर रानांदगांव, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी करते हुए एक-दो स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना जताई है। इससे भीषण गर्मी से बेहाल प्रदेशवासियों ने राहत की सांस ली है। सरगुजा में जहां 25.2 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकाड किया गया है तो वहीं जशपुर में 26.0, बिलासपुर में 27.0, कोरबा में 26.6, रायगढ़ में 26.8, मुंगेली में 26.4, रायगढ़ में 26.8, रायपुर में 24.3, जांजगीर में 16.1, बलौदाबाजार में 26.6, महासमुंद में 24.8, दुर्ग में 24.4, बालोद में 24.5, राजनांदगांव में 25.0, बालोद में 24.5, कांकेर में 26.6, रायपुर में 23.6, बस्तर में 22.8, बीजापुर में 23.6, दंतेवाड़ा में 24.4 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकार्ड किया गया है।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

हिटलर के अनुयायी लोकतंत्र का ज्ञान न बांटें : मरकाम

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने विधानसभा सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि हिटलर के अनुयायी लोकतंत्र का ज्ञान बांट रहे हैं, यह बहुत विचित्र बात है। इनके शाह और शहंशाह देश भर में लोकतंत्र की हत्या पर आमादा हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनी गई सरकारों को अस्थिर करने सीबीआई, आईटी, ईडी, एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसियों को भाजपा का एजेंट बना रखा है। राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ करने इन्हीं एजेंसियों के जरिए धमकाया जाता है और टूटने के बाद सारे पाप धुल जाते हैं। एजेंसियां वहां से बोरिया बिस्तर समेट कर अगले पड़ाव पर निकल पड़ती हैं।छत्तीसगढ़ में भी यही हो रहा है। लोकतांत्रिक सरकार को अस्थिर करने के लिए सारे फार्मूले अख्तियार किए गए हैं और नेता प्रतिपक्ष यहां लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, यह लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि विधायिका का कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार सम्मान करती है। विधायिका पर भरोसा तो भाजपा को नहीं है जो छत्तीसगढ़ की महिला सांसदों को राज्यसभा से घसीट कर बाहर कर देती है। अडानी के खिलाफ आवाज उठाने पर राहुल गांधी को संसद से बाहर करवा देती है। लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है, यह भाजपा ही कर रही है। विधायिका पर किसे भरोसा नहीं है।

भूपेश है तो भरोसा है अभियान चलाएंगे युवक कांग्रेसी

रायपुर। भाजपा एक तरफ जहां चुनाव के मिशन पर लग चुकी है अब कांग्रेस भी एक्टिव हो रही है। सियासत के ग्राउंड जीरो पर कांग्रेस नेता निकलेंगे और अभियान चलाया जाएगा। अभियान को नाम दिया गया है भूपेश है तो भरोसा है। इस अभियान के तहत यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता 50 लाख से अधिक घरों में डोर टू डोर जाकर सरकार की योजनाओं का प्रचार करेंगे।इसे लेकर रायपुर में युवा कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने बताया कि इसी महीने हम सभी 90 विधानसभाओं में ये अभियान चलाएंगे। लोगों के घरों पर जाकर सरकार की योजनाओं के बारे में पॉम्पलेट बांटे जाएंगे, साथ ही हितग्राही पंजीकरण फॉर्म पर ऑफलाइन एवं ऑनलाइन जनता की जानकारी भी ली जाएगी।अगर लोगों को सरकारी योजनाओं को लेकर किसी तरह की समस्या आ रही है उसे भी दूर करने उनकी जानकारी शासन को दी जाएगी। इसके लिए युवा कांग्रेस ने रजिस्ट्रेशन कॉल नंबर भी जारी किया है नंबर 90900-29090 इस पर मिस कॉल कर छत्तीसगढ़ की जनता अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती है। रजिस्ट्रेशन कराने वालों तक यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता योजनाओं की जानकारी भी पहुंचाएंगे।यूथ कांग्रेस अपने वॉलेंटियर्स को इसके लिए ट्रेनिंग दे रही है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 11 लोक सभा में बांटा गया है और इन 11 लोक सभाओं में ये अभियान चलेगा। अभियान को जुलाई के दूसरे सप्ताह में जल्द ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम लॉन्च करेंगे। 14 जुलाई को अंतिम ट्रेनिंग प्रोग्राम है।

युवती का अपहरण लव जिहाद का गंभीर मामला : अमित

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमित साहू ने गरियाबंद जिले में एक सनातनी युवती के अपहरण को लव जिहाद का गंभीर मामला बताते हुए पुलिस की उदासीनता को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। श्री साहू ने कहा कि यह मामला प्रदेश सरकार के सनातन विरोधी रवैए और एजेंडे को एक बार फिर बेनकाब कर रहा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री साहू ने कहा कि प्रदेश सरकार का यह सनातन-विरोधी रवैया कवर्धा से चलकर सरगुजा, नारायणपुर बस्तर से होते हुए बिरनपुर तक पहुंचा था और अब यह मामला गरियाबंद जिले के छुरा तक पहुंच गया है। श्री साहू ने कहा कि गरियाबंद जिले की एक सनातनी युवती का अपहरण सज्जाद नामक एक युवक द्वारा किए जाने का मामला सामने आया है। उक्त युवती के परिजन पिछले पांच दिनों से थाने के चक्कर लगाकर गुहार कर रहे हैं कि उनके परिवार की युवती की पतासाजी करके उनकी बेटी को उनके सुपुर्द किया जाए। लेकिन, पांच दिन बाद भी प्रदेश की भूपेश-सरकार के पुलिस महकमे के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। युवती के परिजन अपनी बेटी की सकुशल वापसी की गुहार लगाते भटक रहे हैं। यह घटना स्पष्ट करती है कि प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लगातार बढ़ावा दे रही है और ऐसे आपराधिक तत्वों को निरंतर पुलिस का संरक्षण किसी-न-किसी रूप में मिल रहा है।

किरंदुल-विशाखापट्टनम रेलवे ट्रैक पर गिरी चट्टान

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में किरंदुल-विशाखापट्टनम रेलवे ट्रैक पर चट्टान गिरने से ये रेल मार्ग 12 जुलाई तक बंद हो गया है। सोमवार रात से अफसर ट्रैक से मलबा हटाने में जुटे हैं। किरंदुल से जगदलपुर होते हुए विशाखापट्टनम जाने वाली पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कोत्तावालसा-किरंदुल रेल लाइन रेल लाइन पर दौड़ने वाली कुछ ट्रेनों का रूट डायवर्ट भी किया गया है।रेलवे के अफसरों ने बताया कि, अरकू रेलवे स्टेशन के नजदीक चिमड़ीपल्ली और बोर्रागुहालु के बीच लैंडस्लाइड हुआ है। सोमवार की देर शाम बड़ी-बड़ी चट्टानें टूटकर पटरी पर गिर गई। जिसकी वजह से मार्ग बाधित हो गया है। इस मामले की जानकारी मिलते ही अफसर खुद एक्सीडेंट रिफिल ट्रेन लेकर मौके पर पहुंचे। रात से ही मार्ग बहाल करने का काम किया जा रहा है। अफसरों की मानें तो इस काम में 24 घंटे का वक्त लग सकता है।बस्तर को विशाखापट्टनम से जोड़ने वाला यह इकलौता रेलवे मार्ग है। यहां से हर दिन सैकड़ों की संख्या में लोग यात्री ट्रेन से सफर करते हैं। किरंदुल से विशाखापट्टनम तक केवल 2 यात्री ट्रेनें चलती हैं। एक किरंदुल-विशाखापट्टनम नाइट एक्सप्रेस और एक किरंदुल-विशाखापट्टनम पैसेंजर ट्रेन है। इसके अलावा हर दिन करीब 15 से ज्यादा मालगाड़ियों की आवाजाही होती है।लैंडस्लाइड होने के बाद इस मार्ग से गुजरने वाली किरंदुल-विशाखापट्टनम पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही इस मार्ग पर दौड़ने वाली विशाखापट्टनम-कोरापुट पैसेंजर ट्रेन को भी रद्द कर दिया गया है।

पीडीएस घोटाला : कार्रवाई को सार्वजनिक करें सरकार: शर्मा

रायपुर। छत्तीसगढ़ बीजपी प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने प्रदेश सरकार से पीडीएस मामले में अब तक हुई जांच वसूली और दोषी अफसरों पर कार्रवाई को सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 600 करोड़ रुपए के इस पीडीएस घोटाले को विधानसभा में स्वीकार करते हुए प्रदेश सरकार ने विधानसभा कमेटी के बजाय अधिकारियों से जांच कराने की बात कही थी। विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने यह मामला उठाया था और अतिशेष स्टॉक को लेकर खाद्य विभाग और जिला प्रशासन के आंकड़ों में अंतर होने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि 59 लाख मीट्रिक टन चावल गायब होने की जांच कराने की मांग करके डॉ. सिंह ने बड़े घोटाले के खुलासे का दावा किया था। विधानसभा में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने स्वीकार किया था कि 4 हजार 952 राशन दुकानों में 41 हजार टन चावल की कमी पाई गई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि पीडीएस के इस घोटाले में अधिकारियों और कर्मचारियों की संलिप्तता को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने अधिकारियों के बजाय विधानसभा की कमेटी से इसकी जांच कराने की मांग विधानसभा में की थी, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर उन अधिकारियों से इस घोटाले की जांच कराने की बात कही, जिन्होंने इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया था।

शराब कोचियो ने शराब न बेचने का किया वादा, आंदोलन स्थगित

रायपुर। शराब कोचियो ने शराब न बेचने का किया वादा , रायपुर । खरोरा थाना क्षेत्र के? अंतर्गत आने वाले ग्राम असौंदा में ग्रामीणों द्वारा अवैध शराब बिक्री के खिलाफ बीते एक सप्ताह से गांधीवादी तरीके से छेड़ा गया आंदोलन कोचियो द्वारा अब अवैध शराब न बेचने के वादे के बाद ग्रामीणों ने इन पर सतत् निगरानी के निर्णय के साथ फिलहाल स्थगित कर दिया है। आसन्न रविवार को समीक्षा पश्चात् आवश्यकता महसूस होने पर आगामी आंदोलन की रूपरेखा ग्रामवासियों द्वारा तय की जावेगी ।

ज्ञातव्य हो कि ग्राम में 8 - 10 अवैध शराब विक्रेताओं ने ग्राम से गुजरने वाले मुख्य सड़क मार्ग सहित ग्राम के गली कूचों में अघोषित शराब भट्ठी का माहौल बना रखा था । इसकी वजह से न केवल ग्राम के निवासी वरन् सड़क मार्ग से गुजरने वाले राहगीर भी परेशान हो चले थे। ग्रामवासी सहित आसपास के ग्राम प्रमुखों के आग्रह पर सरपंच राजेश साहू ने पंचायत प्रतिनिधियों से चर्चा पश्चात् ग्रामवासियों सहित आसपास के ग्राम प्रमुखों की एक बैठक बीते 2 जुलाई को आहूत की थी । बैठक में इसके खिलाफ उपजे आक्रोश के मद्देनजर ग्रामीणों के समर्थन को देखते हुये महिलाओं ने मोर्चा खोल प्रतिदिन रैली निकाल लिप्त तत्वों को समझाईश देने व ग्राम में जागरूकता फैलाने के साथ कोचियो को इस धंधे से तौबा करने 7 दिन का अल्टिमेटम देने निर्णय लिया था। इसके बाद से महिलाये ग्राम प्रमुखों के साथ प्रतिदिन ग्राम के गली कूचों में भ्रमण कर कोचियो को समझाईश पर समझाईश दे रहे थे। ग्रामीणों के अनुसार इसके चलते 2 कोचियो को छोड़ शेष ने ग्रामवासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुये शराब बेचना बंद कर दिया था । ये 2 कोचिये ग्रामवासियों को आश्वासन देने के बाद भी गुपचुप तरीके से शराब बेचने से बाज नहीं आ रहे थे। इधर दिन प्रतिदिन रैली में शिरकत करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही थी व बीते कल सोमवार को तो आयोजित रैली में तो बच्चों ने भी भाग ले शराब के खिलाफ अपना इरादा जाहिर कर दिया था। इस बीच ग्रामीणों ने रैली के दौरान पुलिसिया बल उपलब्ध कराने व ग्राम में गश्त कराने थाना प्रभारी सहित विधानसभा नगर पुलिस अधीक्षक उदयन बेहार को ज्ञापन सौंपा था व पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल को शराब विरोधी मुहिम में जुटे किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेन्द्र शर्मा के साथ जा ज्ञापन सौंपने की तैय्यारी में थे ।

बच्चों को पढ़ाने सरल और रोचक तरीके का करे उपयोग : कलेक्टर

रायपुर। बच्चों को बचपन में यदि कोई सीख दी जाती है। उसे इस समय जो पढ़ाया-सिखाया जाता है और वह उसे बेहतर कैरियर बनाने के काम आता है। वहीं अच्छे भविष्य की नींव रहती है। बच्चे को सरल ढंग से कुछ सिखाया जाता है वह आसानी से सीखता है, इसलिए बच्चों को शिक्षा देने के लिए सहज और रोचक तरीके का उपयोग करना चाहिए। यह बात कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने सम्पर्क फाउंडेशन के रेडक्रास सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में कही। इस अवसर पर उन्होंने सम्पर्क फाउंडेशन के ब्रोशर और ग्रेड 1 से 3 की गणित और अंग्रेजी के पुस्तकों का विमोचन भी किया।

कलेक्टर डॉ भुरे ने कहा कि संपर्क फाउंडेशन द्वारा जो किट और टूल्स स्कूलों में दिए जा रहे है। उससे बच्चों को उनके पढ़ाई अच्छा सहयोग मिलेगा। साथ ही वे पाठ्यक्रम को आसानी से समझ सकेंगे। शिक्षकों को भी इससे पढ़ाने में मदद मिलेगी और हमें बेहतर परिणाम मिलने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि सामान्यत: यह भी अनुभव किया गया है कि शासकीय संस्थाओं के साथ अशासकीय संस्थांऐ मिलकर कार्य करती है तो नई तकनीक सीखने मिलती है और दक्षता भी आती है।

नीति आयोग के पूर्व विशेष सचिव एवं सम्पर्क फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. के राजेश्वर राव ने कहा कि हमारी संस्था का उद्देश्य शिक्षा का नवाचार लाना है। हमारे द्वारा स्कूलों में सम्पर्क टी.वी. ऑडियो बॉक्स, अंग्रेजी और गणित के किट प्रदान किये जा रहे है। सम्पर्क टी.वी ऐसा डिवाइस है जो बिना इंटरनेट के चल सकता है आसानी से टी.वी से कनेक्ट किया जा सकता है। इसमें कक्षावार विषयवार वीडियो विजुअल डाले गए है। यहां बच्चों पर केंद्रित पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है, जो बच्चों को आसानी से सिखने में मदद करती है। साथ ही एक ऑडियो बॉक्स भी शामिल है जिसमें पाठ्क्रम की रिकॉर्डिंग रहती है। जिसे सुनकर बच्चा आसानी से सीख सकता है।गौरतलब संस्था के प्रतिनिधियों ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के रुप में इसे रायपुर जिले में संचालित किया जा रहा है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.